

DATE 12.02.2026 TIME 11.30 AM PERIOD 3

subject family law

source of hindu law

ancient

a shruti 4 vedas

b smirit

c digest and commentaries

d customs

modern

a judicial decision

b legislation

c justice equal and good concern

a **SHRUTI**

The term **Shruti** is derived from the Sanskrit word “*Shru*”, which means “**to hear.**” Shruti literally means “**that which is heard.**” In Hindu Law, **Shruti** is considered the **primary and paramount source** of law. It is believed to contain the divine revelations that were heard by ancient sages (Rishis) from God and passed down orally from generation to generation.

“श्रुति” शब्द संस्कृत के “श्रु” धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है “सुनना”। इसलिए श्रुति का शाब्दिक अर्थ है—“जो सुना गया हो”। हिंदू विधि में श्रुति को विधि का प्रमुख एवं सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें दैवीय ज्ञान निहित है, जिसे प्राचीन ऋषियों (Rishis) ने भगवान से सुना और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया।

Shruti mainly consists of the **Vedas**, which are:

- Rigveda
- Yajurveda
- Samaveda
- Atharvaveda

Each Veda is further divided into:

1. Samhitas
2. Brahmanas
3. Aranyakas
4. Upanishads

Since Shruti is regarded as divine and eternal, it holds the **highest authority** in the hierarchy of Hindu law sources. All other sources, such as Smriti (that which is remembered), customs, and judicial decisions, must conform to Shruti.

"The term Shruti is derived from the word 'Shru', which means 'to hear'. It is considered to be the primary and paramount source of Hindu Law."

चूँकि श्रुति को दैवीय और शाश्वत माना जाता है, इसलिए हिंदू विधि के स्रोतों की श्रेणी में इसका सर्वोच्च स्थान है। अन्य सभी स्रोत, जैसे स्मृति (जो याद किया गया हो), प्रथाएँ (customs) और न्यायिक निर्णय, श्रुति के अनुरूप होने चाहिए।

Smriti (स्मृति) The term **Smriti** is derived from the Sanskrit word "Smri", which means "to remember." Smriti literally means "that which is remembered."

In Hindu Law, **Smriti** is considered the **second important source** after Shruti. While Shruti is believed to be divine revelation, Smriti is based on the **traditions, teachings, and interpretations** given by ancient sages. It explains and elaborates the principles contained in the Vedas.

"स्मृति" शब्द संस्कृत के "स्मृ" (Smri) धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है "याद रखना"। इसलिए स्मृति का शाब्दिक अर्थ है—"जो याद रखा गया हो"। हिंदू विधि में स्मृति को श्रुति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जहाँ श्रुति को दैवीय (ईश्वरीय) ज्ञान माना जाता है, वहीं स्मृति प्राचीन ऋषियों द्वारा दी गई परंपराओं, शिक्षाओं और उनकी व्याख्याओं पर आधारित होती है। स्मृति, वेदों में निहित सिद्धांतों को स्पष्ट और विस्तृत रूप में समझाती है।

Main Smritis:

- Manusmriti
- Yajnavalkya Smriti
- Narada Smriti

Among these, **Manusmriti** is considered the oldest and most important.

Importance in Hindu Law:

- Smriti provides detailed rules regarding **marriage, inheritance, property, duties, and punishments**.
- When there is no clear rule in Shruti, Smriti is followed.
- If there is a conflict between Shruti and Smriti, **Shruti prevails**.

कानूनी संदर्भ में स्मृति के बारे में मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

1. स्मृति का अर्थ (Meaning of Smriti)

- 'स्मृति' शब्द संस्कृत की 'स्मृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है "याद किया हुआ"।
- इन्हें ऋषियों द्वारा वेदों (श्रुति) के ज्ञान को याद करके और अपनी बुद्धि से संकलित करके लिखा गया था।
- जहाँ श्रुति को 'ईश्वरीय' माना जाता है, वहीं स्मृति को 'मानव निर्मित' माना जाता है।

2. स्मृतियों का वर्गीकरण (Classification)

स्मृतियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:

- **धर्मसूत्र (Dharmasutras):** ये गद्य (Prose) में लिखे गए हैं (जैसे- गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब धर्मसूत्र)।
- **धर्मशास्त्र (Dharmashastras):** ये पद्य या श्लोकों (Poetry) में लिखे गए हैं।

3. प्रमुख स्मृतियाँ (Main Smritis) कानूनी इतिहास में तीन स्मृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं:

- **मनुस्मृति (Manusmriti):** यह सबसे प्राचीन और आधारभूत स्मृति है। इसमें ऋण, उत्तराधिकार, विवाह और दंड जैसे 18 विधिक विषयों का वर्णन है।
- **याज्ञवल्क्य स्मृति (Yajnavalkya Smriti):** यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक व्यवस्थित और संक्षिप्त है। आधुनिक हिंदू कानून के कई सिद्धांत इसी पर आधारित हैं।
- **नारद स्मृति (Narada Smriti):** यह मुख्य रूप से व्यवहार (Civil Law) और अदालती प्रक्रिया पर केंद्रित है।

4. स्मृति के तीन भाग (Three Parts of Smriti Rules)

स्मृतियों में कानून को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. **आचार (Achara):** सामाजिक और नैतिक व्यवहार के नियम (जैसे- विवाह)।
2. **व्यवहार (Vyavahara):** नागरिक और आपराधिक कानून (जैसे- संपत्ति विवाद)।
3. **प्रायश्चित (Prayaschit):** गलत कार्यों के लिए दंड या धार्मिक शुद्धि।

5. आधुनिक महत्व यद्यपि आज हिंदू कानून संहिताबद्ध (Codified) हो चुका है, लेकिन उत्तराधिकार, विवाह और गोद लेने जैसे विषयों में स्मृतियों के सिद्धांत आज भी हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) के मूल आधार के रूप में कार्य करते हैं।

मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में तुलनात्मक अंतर

आधार	मनुस्मृति (Manusmriti)	याज्ञवल्क्य स्मृति (Yajnavalkya Smriti)
काल (Period)	यह सबसे प्राचीन स्मृति है (लगभग 200 ई.पू. से 200 ईस्वी)।	यह मनुस्मृति के बाद की रचना है (लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी)।
संरचना (Structure)	इसमें 12 अध्याय और लगभग 2,694 श्लोक हैं।	यह अधिक संक्षिप्त है, इसमें 3 अध्याय और केवल 1,010 श्लोक हैं।

विभाजन	विषयों का विभाजन व्यवस्थित नहीं है, धार्मिक और कानूनी नियम मिले हुए हैं।	इसे स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा गया है: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त।
राजा की शक्ति	राजा को 'दैवीय उत्पत्ति' (Divine Right) का प्रतीक माना गया है।	राजा को कानून के अधीन माना गया है, न कि उससे ऊपर।
स्त्रियों का स्थान	तुलनात्मक रूप से अधिक रूढ़िवादी है।	स्त्रियों के प्रति अधिक उदार है; उन्हें संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है।
कानूनी प्रक्रिया	इसमें प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) पर कम जोर दिया गया है।	इसमें साक्ष्य (Evidence) और अदालती प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है।

(Exam Notes)

- मनुस्मृति का महत्व:** इसे 'मानव धर्मशास्त्र' भी कहा जाता है। यह हिंदू कानून का मूल स्तंभ है। इसमें ऋण, उत्तराधिकार और दंड जैसे 18 शीर्षकों (Titles of Law) का वर्णन है।
- याज्ञवल्क्य स्मृति की विशेषता:** यह अपनी स्पष्टता और संक्षिप्तता के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध टीका 'मिताक्षरा' (विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित) इसी स्मृति पर आधारित है, जो आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में उत्तराधिकार कानून का आधार है।
- स्मृति के प्रमुख लेखक:** याज्ञवल्क्य ने 20 स्मृति-कारों की सूची दी है, जिनमें अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनास, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ शामिल हैं।

Meaning of Digest and Commentaries in Hindu Law In Hindu Law, **Digest and Commentaries** are considered important sources after Shruti and Smriti. They explain, interpret, and clarify the rules given in the Smritis.

1 Commentaries (टीकाएँ) Commentaries are explanations written by learned scholars on Smriti texts to remove doubts and clarify meanings.

- They interpret difficult verses.
- They adapt ancient rules to changing social conditions.
- Courts have relied on them in deciding cases.

Important Commentaries:

- Mitakshara – Written by Vijnaneshwara on Yajnavalkya Smriti.
- Dayabhaga – Written by Jimutavahana.

These two schools (Mitakshara and Dayabhaga) became the foundation of Hindu law in different parts of India.

2 Digest (निबंध) A **Digest** is a compilation or summary of rules collected from various Smritis and commentaries.

- It gathers opinions of different scholars.
- It compares and reconciles conflicting views.
- It presents the law in a systematic manner.

In simple words:

👉 **Commentary = Explanation of one Smriti**

👉 **Digest = Collection and summary of many Smritis and commentaries**

हिंदू विधि (Hindu Law) के विकास में **भाष्य (Commentaries)** और **निबंध (Digests)** का बहुत बड़ा महत्व है। सरल शब्दों में इनका अर्थ नीचे दिया गया है:

1. भाष्य (Commentaries)

- **अर्थ:** जब किसी विशेष **स्मृति** (जैसे मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति) की व्याख्या करने के लिए उस पर विस्तृत टीका लिखी गई, तो उसे 'भाष्य' कहा गया। [5.1]
- **उद्देश्य:** स्मृतियों की भाषा कठिन और संक्षिप्त थी। भाष्यकारों ने उनके अर्थ को सरल बनाया और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी नई व्याख्या की। [5.1]
- **उदाहरण:**
 - **मिताक्षरा (Mitakshara):** यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर **विज्ञानेश्वर** द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध भाष्य है। [5.1]
 - **मनुभाष्य:** मेधातिथि द्वारा मनुस्मृति पर लिखी गई टीका।

2. निबंध (Digests)

- **अर्थ:** जब किसी एक स्मृति को आधार बनाने के बजाय, **कई स्मृतियों** से अलग-अलग विषयों को इकट्ठा करके एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा गया, तो उसे 'निबंध' कहा गया। [5.1]
- **उद्देश्य:** निबंधों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्मृतियों के बीच के विरोधाभासों (Contradictions) को दूर करना और एक सर्वसम्मत नियम बनाना था। [5.1]
- **उदाहरण:**

- **दायभाग (Dayabhaga):** यह जीमूतवाहन द्वारा रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है, जो मुख्य रूप से उत्तराधिकार के नियमों पर केंद्रित है। [5.1]
- **वीरमित्रोदय:** मित्र मिश्र द्वारा रचित।

भाष्य और निबंध में मुख्य अंतर

आधार	भाष्य (Commentaries)	निबंध (Digests)
आधार	यह किसी एक विशेष स्मृति पर आधारित होता है।	यह अनेक स्मृतियों का सार या संकलन होता है।
कार्य	यह मूल ग्रंथ (स्मृति) की व्याख्या करता है।	यह विभिन्न ग्रंथों के नियमों में सामंजस्य बिठाता है।
स्वतंत्रता	यह मूल पाठ (Original Text) से बंधा होता है।	यह लेखक के अपने दृष्टिकोण से अधिक स्वतंत्र होता है।

महत्व: आज भी भारत में हिंदू कानून के दो मुख्य संप्रदाय (Schools) — **मिताक्षरा** और **दायभाग** — इन्हीं भाष्यों और निबंधों की देन हैं। [5.1]

Modern Sources of Hindu Law Modern sources of Hindu Law are those sources which developed during and after British rule in India. These sources have modified and codified traditional Hindu law.

1. Judicial Decisions (Precedents)

Judicial decisions are one of the most important modern sources of Hindu law. Under the principle of **stare decisis**, the decisions of higher courts are binding on lower courts.

The decisions of:

- Supreme Court of India
- High Courts of India

have greatly contributed to the development and interpretation of Hindu law.

Example: Courts have interpreted customs, marriage laws, succession rights, etc.

2. Legislation (Statutory Law)

Legislation is the most important modern source. After independence, Hindu law was codified and reformed by Parliament.

Major Acts include:

- Hindu Marriage Act
- Hindu Succession Act
- Hindu Minority and Guardianship Act
- Hindu Adoptions and Maintenance Act

These Acts brought uniformity and removed many old discriminatory practices.

3. Justice, Equity and Good Conscience When there is no rule in Shruti, Smriti, Custom, or legislation, courts apply the principle of justice, equity, and good conscience. This principle was introduced during British rule.

4. Custom Custom continues to be a modern source if it is:

- Ancient
- Certain
- Reasonable
- Not opposed to public policy

Courts recognize customs if they are properly proved.

हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत

हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत वे हैं जो ब्रिटिश शासन के बाद विकसित हुए और जिनसे हिन्दू कानून में संशोधन एवं संहिताकरण हुआ।

1. न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions)

न्यायालयों के निर्णय आधुनिक हिन्दू विधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। **Stare Decisis** के सिद्धांत के अनुसार उच्च न्यायालयों के निर्णय निम्न न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

- Supreme Court of India
- High Courts of India

इन न्यायालयों ने विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, अभिभावकत्व आदि विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्या की है।

विधायन (Legislation) स्वतंत्रता के बाद संसद ने हिन्दू कानून को संहिताबद्ध किया। प्रमुख अधिनियम:

- Hindu Marriage Act
- Hindu Succession Act
- Hindu Minority and Guardianship Act
- Hindu Adoptions and Maintenance Act

इन अधिनियमों ने समानता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया।

न्याय, समता और सद्बिबेक (Justice, Equity and Good Conscience) जहाँ कोई स्पष्ट नियम उपलब्ध नहीं होता, वहाँ न्यायालय न्याय, समता और सद्बिबेक के सिद्धांत को लागू करते हैं।

प्रथा (Custom) यदि कोई प्रथा:

- प्राचीन हो
- निश्चित हो
- उचित हो
- लोकनीति के विरुद्ध न हो

तो न्यायालय उसे मान्यता देते हैं।

Hindu Marriage Act, 1955 – The **Hindu Marriage Act, 1955** is a codified law enacted to regulate marriage among Hindus. It applies to Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs.

◆ **Important Features:**

1 Conditions of a Valid Marriage (Section 5)

- Monogamy (no living spouse at the time of marriage)
- Sound mind
- Marriageable age: 21 years (male), 18 years (female)
- Parties not within prohibited relationship (unless custom permits)

2 Restitution of Conjugal Rights (Section 9)

If one spouse withdraws without reasonable cause, the other may seek court relief.

3 Judicial Separation (Section 10)

Court allows spouses to live separately without dissolving the marriage.

4 Divorce (Section 13)

Grounds include:

- Adultery
- Cruelty

- Desertion
- Conversion
- Mental disorder
- Communicable disease (earlier provision amended)
- Mutual consent (Section 13B)

5 Maintenance & Alimony (Sections 24 & 25) Financial support during and after proceedings.

Hindu Marriage Act, 1955 (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू होता है।

◆ मुख्य प्रावधान:

1 वैध विवाह की शर्तें (धारा 5)

- एकपत्नी प्रथा (पति/पत्नी जीवित न हो)
- मानसिक रूप से स्वस्थ
- आयु: पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष
- निषिद्ध संबंध में विवाह नहीं (जब तक प्रथा अनुमति न दे)

2 दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9)

यदि कोई पति/पत्नी बिना उचित कारण अलग रहता है, तो दूसरा पक्ष न्यायालय जा सकता है।

3 न्यायिक पृथक्करण (धारा 10)

विवाह समाप्त नहीं होता, परंतु अलग रहने की अनुमति मिलती है।

4 तलाक (धारा 13)

तलाक के आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार
- आपसी सहमति (धारा 13B)

5 भरण-पोषण (धारा 24, 25) कार्यवाही के दौरान और बाद में आर्थिक सहायता।

Hindu marriage act 1955. **1. Introduction** The Hindu Marriage Act, 1955 was enacted to amend and codify the law relating to marriage among Hindus. It came into force on **18 May 1955**. It applies to:

- Hindus
- Buddhists
- Jains
- Sikhs

(Not applicable to Muslims, Christians, Parsis, and Jews.)

2. Objectives

- To codify Hindu marriage law
 - To provide conditions for valid marriage
 - To introduce divorce provisions
 - To promote monogamy
 - To protect rights of women
-

3. Conditions for Valid Marriage (Section 5) A Hindu marriage is valid if:

1. Neither party has a living spouse (Monogamy)/**bigamy.**
 2. Both parties are of sound mind
 3. Groom must be 21 years, bride 18 years
 4. Parties are not within prohibited degrees
 5. Not sapindas of each other (unless custom permits)
-

case for bigamy. "Priya V Suresh 1971" refers to the landmark Indian Supreme Court case **Smt. Priya Bala Ghosh vs. Suresh Chandra Ghosh**, decided on March 4, 1971. This case is a fundamental authority in Indian family law regarding the proof required for the offence of **bigamy** under Section 494 of the Indian Penal Code.

Key Rulings of the Case

- **Strict Proof of Marriage:** The Court ruled that for a conviction of bigamy, the prosecution must prove that the second marriage was performed with all the **essential religious rites** and ceremonies (such as *Homa* and *Saptapadi* for Hindu marriages).
- **Insufficiency of Admissions:** A crucial aspect of this judgment is that a mere **admission** by the accused that they have remarried is not sufficient for a conviction. The second marriage must be proven as a fact through evidence of its solemnisation.
- **Validity Requirement:** Under [Section 17 of the Hindu Marriage Act](#), a second marriage is only void—and thus bigamous—if it would have been a valid marriage but for the existence of the first spouse. If essential ceremonies are missing, the "marriage" is not legally a marriage at all, meaning the charge of bigamy cannot stand.

Case Details

- **Parties:** Priya Bala Ghosh (Appellant) vs. Suresh Chandra Ghosh (Respondent).
- **Bench:** Justices C.A. Vaidyalingam and A.N. Ray.
- **Outcome:** The Supreme Court **upheld the acquittal** of the husband because the prosecution failed to prove that the essential ceremonies for the second marriage had been performed

यह मामला **श्रीमती प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष (1971)** के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय कानून में **द्विविवाह (Bigamy)** के अपराध को साबित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मामले के मुख्य बिंदु:

- **अनिवार्य धार्मिक रस्में:** [सुप्रीम कोर्ट](#) ने यह फैसला सुनाया कि द्विविवाह (IPC की धारा 494) के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि दूसरी शादी **पूरी कानूनी और धार्मिक रस्मों** (जैसे हिंदू विवाह में 'सप्तपदी' और 'होम') के साथ संपन्न हुई थी।
- **सिर्फ स्वीकारोक्ति काफी नहीं:** अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी केवल यह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो सिर्फ इस बयान के आधार पर उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी शादी का ठोस सबूत होना जरूरी है।

- **कानूनी वैधता:** हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत, दूसरी शादी तभी शून्य और दंडनीय मानी जाती है जब वह कानूनी रूप से संपन्न हुई हो। यदि आवश्यक रस्में नहीं निभाई गईं, तो कानून की नजर में वह 'शादी' ही नहीं है।

मामले का परिणाम: इस मामले में, आरोपी (पति) को बरी कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दूसरी शादी के समय सभी आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से किए गए थे।

case for mental stability. Alka Sharma v. Avinash Chandra (1991)

◆ **Legal Issue:** Whether a husband can be convicted for bigamy without strict proof of valid performance of essential marriage ceremonies.

◆ Principle Laid Down:

The Court held that:

- For establishing bigamy, mere cohabitation or admission is not enough.
- The second marriage must be proved to have been solemnized with essential Hindu rites and ceremonies.
- If essential ceremonies like *Saptapadi* are not proved, the offence under Section 494 IPC is not made out.

Thus, strict proof of a valid second marriage is necessary.

Legal Position Under Law Under Section 5(i) of the Hindu Marriage Act: - A marriage is valid only if neither party has a living spouse at the time of marriage.

If violated:


- The marriage is void (Section 11)
- Punishable under Section 494 IPC

Alka Sharma v. Avinash Chandra (1991) क्या बिना विवाह की आवश्यक रस्मों के प्रमाण के, पति को द्विविवाह (Bigamy) का दोषी ठहराया जा सकता है?

◆ **न्यायालय का निर्णय:**

न्यायालय ने कहा:

- केवल साथ रहना (cohabitation) या स्वीकारोक्ति पर्याप्त नहीं है।
- दूसरी शादी को वैध सिद्ध करने के लिए आवश्यक हिन्दू रीति-रिवाज (जैसे सप्तपदी) का प्रमाण आवश्यक है।
- यदि आवश्यक संस्कार सिद्ध नहीं होते, तो धारा 494 IPC के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होगा।

 **Important for Exam** This case supports the same principle as:

- Bhaurao Shankar Lokhande v. State of Maharashtra
 - Kanwal Ram v. Himachal Pradesh Administration
-
-

age of the person in relation of marriage. **Maninder Kaur v. Major Singh**

Issue:

Whether a marriage performed below the prescribed age under the **Hindu Marriage Act** is **void** or merely punishable?

◆ **Legal Provision Involved:** -**Section 5(iii)** of the Hindu Marriage Act

- Groom: 21 years
- Bride: 18 years

(At that time, the prescribed age was lower; later amended.)

Facts:

- The marriage was performed when one of the parties had not attained the required minimum age.
- The question before the court was whether such a marriage becomes invalid.

Judgment / Principle: The Court held:

1. Marriage in contravention of the prescribed age is **not void** under the Hindu Marriage Act.
2. Such marriage is **valid**, but punishable under Section 18 of the Act.
3. Age condition is **not included** under Sections 11 (void marriages) or 12 (voidable marriages).

4. Therefore, minority does not automatically invalidate the marriage.

Important Legal Point (Exam Oriented):

👉 Under Hindu Marriage Act, violation of age requirement does **not** make the marriage void. 👉 It only attracts **penalty**.

Maninder Kaur v. Major Singh (1972) क्या कम आयु में किया गया विवाह शून्य (Void) है?

◆ **निर्णय:** न्यायालय ने कहा:

- आयु संबंधी शर्त (धारा 5(iii)) का उल्लंघन विवाह को शून्य नहीं बनाता।
- ऐसा विवाह वैध रहेगा।
- केवल धारा 18 के तहत दंडनीय होगा।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- ✓ आयु की शर्त का उल्लंघन = विवाह वैध रहेगा
- ✓ परंतु दंड लागू होगा
- ✓ शून्य विवाह केवल धारा 11 में दिए गए मामलों में होता है

Section 18 – Punishment for contravention of certain conditions Under the Hindu Marriage Act Section 18 provides punishment if the conditions of **Section 5** are violated.

Section 18(a) – Prohibited Relationship / Sapinda

If marriage is solemnized:

- Within **prohibited degrees of relationship**, or
- Between **sapindas** (without valid custom),

👉 **Punishment:**

- **Simple imprisonment up to 1 month**, or
- **Fine up to ₹1,000**, or
- **Both.**

Section 18(b) – Age Requirement (Section 5(iii)) If marriage is solemnized in violation of the **minimum age condition**: (Current age: Groom – 21 years, Bride – 18 years)

👉 Punishment:

- Simple imprisonment up to 2 years, or
- Fine up to ₹1 lakh, or
- Both. (As amended by later laws)

Important Exam Points

- ✓ Violation of age condition does **not make marriage void**.
- ✓ It only attracts punishment.
- ✓ Bigamy punishment is under Section 17 (read with IPC 494), not Section 18.

धारा 18 – शर्तों के उल्लंघन पर दंड (हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955)

- ◆ (क) निषिद्ध संबंध / सपिंड विवाह
 - 1 माह तक साधारण कारावास
 - या ₹1000 तक जुर्माना
 - या दोनों
- ◆ (ख) आयु संबंधी शर्त का उल्लंघन
 - 2 वर्ष तक साधारण कारावास
 - या ₹1,00,000 तक जुर्माना
 - या दोनों

4. Ceremonies (Section 7) Marriage must be solemnized according to customary rites and ceremonies. Saptapadi (seven steps) is essential in many cases.

5. Restitution of Conjugal Rights (Section 9) If one spouse withdraws without reasonable cause, the other may file a petition for restitution.

6. Judicial Separation (Section 10)

Court permits spouses to live separately without dissolving marriage.

7. Divorce (Section 13) Grounds for divorce include:

- Adultery
 - Cruelty
 - Desertion (2 years)
 - Conversion
 - Mental disorder
 - Communicable disease (as amended)
 - Renunciation
 - Presumption of death
-

8. Void and Voidable Marriage Void Marriage (Section 11):

- Bigamy
- Prohibited relationship

Voidable Marriage (Section 12):

- Impotency
 - Fraud
 - Force
 - Pregnancy by another person
-

9. Maintenance and Alimony (Sections 24 & 25)

Court may grant:

- Interim maintenance
 - Permanent alimony
-

10. Importance It brought major reforms such as:

- Abolition of polygamy
- Legal recognition of divorce

- Protection of women's rights

Restitution of Conjugal Rights Under Section 9 of the Hindu Marriage Act Restitution of Conjugal Rights means the **restoration of marital rights** when one spouse withdraws from the society of the other without reasonable excuse.

Section 9 – Provision Either the husband or wife

- Has withdrawn from the society of the other
- Without reasonable cause

👉 The aggrieved party may file a petition in the District Court.

👉 The court may pass a decree for restitution of conjugal rights.

Essential Conditions

1. Valid marriage must exist.
2. One spouse must have withdrawn.
3. Withdrawal must be without reasonable excuse.
4. Petition must be filed in competent court.

Burden of Proof The burden lies on the person who has withdrawn to prove reasonable excuse.

◆ **Effect of Decree**

- Court orders the spouse to resume cohabitation.
- If decree is not obeyed for **1 year**, it becomes a ground for divorce under Section 13(1A).

Important Case Laws

1. **T. Sareetha v. T. Venkata Subbaiah**
Held Section 9 unconstitutional (violation of privacy).
2. **Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha**
Supreme Court upheld constitutional validity of Section 9.

- ✓ It is a matrimonial remedy.
- ✓ It does not dissolve marriage.
- ✓ Non-compliance for 1 year → Ground for divorce.

दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9) यदि पति या पत्नी बिना उचित कारण के दूसरे से अलग हो जाए, तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

आवश्यक तत्व:

- वैध विवाह
- बिना उचित कारण अलगाव
- न्यायालय की डिक्री

प्रभाव:

- साथ रहने का आदेश
- 1 वर्ष तक पालन न होने पर तलाक का आधार

Judicial Separation Under Section 10 of the Hindu Marriage Act Judicial Separation means a **legal separation** of husband and wife by a court decree, without dissolving the marriage.

The marriage continues to exist, but spouses are not bound to live together.

Grounds (Section 10)

After the 1976 amendment, the grounds for Judicial Separation are the same as for divorce under Section 13, such as:

- Adultery
- Cruelty
- Desertion
- Conversion
- Mental disorder
- Renunciation
- Presumption of death

Essential Points

1. Valid marriage must exist.
2. Petition must be filed in District Court.
3. Court must be satisfied about the grounds.

Effect of Judicial Separation

- ✓ Spouses are not required to cohabit.
- ✓ Marriage is not dissolved.
- ✓ Rights and duties remain, except cohabitation.
- ✓ If no resumption of cohabitation for 1 year → Ground for divorce under Section 13(1A).

Difference Between Judicial Separation and Divorce

Judicial Separation	Divorce
Marriage continues	Marriage dissolved
Temporary relief	Permanent termination
Possible reconciliation	No marital status remains

Important Case **Bipinchandra Jaisingbhai Shah v. Prabhavati** Laid down principles relating to desertion, which apply to judicial separation and divorce.

न्यायिक पृथक्करण (धारा 10) - न्यायालय द्वारा पति-पत्नी को अलग रहने की अनुमति देना, बिना विवाह समाप्त किए।

आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार

प्रभाव:

- ✓ विवाह समाप्त नहीं होता
- ✓ साथ रहने की बाध्यता समाप्त
- ✓ 1 वर्ष तक साथ न रहने पर तलाक का आधार

Nullity of Marriage Under the Hindu Marriage Act

Nullity of marriage means a **declaration by the court that the marriage is null and void.**

It is of two types:

1. **Void Marriage (Section 11)** A marriage is **void from the beginning (void ab initio)** if it violates:

1. **Bigamy** – Either party has a living spouse at the time of marriage.
2. **Prohibited degrees of relationship** (unless custom permits).
3. **Sapinda relationship** (unless custom permits).

👉 Such marriage is treated as if it never existed.

👉 Either party may file a petition for declaration of nullity.

2. **Voidable Marriage (Section 12)**

A marriage is valid until annulled by court. It becomes void only after a decree.

Grounds:

1. Impotency
2. Unsoundness of mind
3. Consent obtained by fraud
4. Consent obtained by force
5. Wife pregnant by another person at the time of marriage

👉 Petition must be filed within prescribed time.

Important Difference

Void Marriage

Automatically invalid

Voidable Marriage

Valid until annulled

Void Marriage	Voidable Marriage
No legal existence	Valid unless challenged
Covered under Section 11	Covered under Section 12

Legitimacy of Children Under Section 16 of the Act: Children of void and voidable marriages are **legitimate**, though property rights are limited to parents' property.

विवाह की शून्यता (Nullity of Marriage)

◆ शून्य विवाह (धारा 11)

- द्विविवाह
- निषिद्ध संबंध
- सपिंड संबंध

👉 विवाह प्रारंभ से ही अमान्य माना जाएगा।

शून्यकरणीय विवाह (धारा 12)

- नपुंसकता
- मानसिक अस्वस्थता
- धोखा
- बल प्रयोग
- विवाह के समय पत्नी का किसी अन्य से गर्भवती होना

👉 न्यायालय की डिक्री के बाद ही अमान्य होगा।

Divorce Under Section 13 of the Hindu Marriage Act **Meaning** - Divorce means the **legal dissolution of marriage** by a decree of the court. After divorce, the marital relationship permanently ends.

Grounds for Divorce (Section 13) A husband or wife may seek divorce on the following grounds:

1. **Adultery**
2. **Cruelty**

3. **Desertion** (for 2 years)
4. **Conversion** to another religion
5. **Unsoundness of mind / mental disorder**
6. **Venereal disease** (as amended)
7. **Renunciation of the world**
8. **Presumption of death** (not heard for 7 years)

Additional Grounds Available to Wife (Section 13(2))

- Husband guilty of rape, sodomy, or bestiality
- Husband has another wife living
- Non-resumption of cohabitation after maintenance decree
- Marriage before 15 years of age (repudiation before 18 years)

Divorce by Mutual Consent (Section 13B) Conditions:

1. Husband and wife living separately for at least 1 year
2. Both agree to dissolve the marriage
3. Petition filed jointly

Court grants divorce after satisfaction.

Divorce after Judicial Separation / Restitution

If no resumption of cohabitation for **1 year** after decree of:

- Judicial separation
- Restitution of conjugal rights

It becomes a ground for divorce (Section 13(1A)).

Important Case Naveen Kohli v. Neelu Kohli Supreme Court recommended inclusion of irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce.

तलाक (धारा 13) तलाक विवाह का न्यायालय द्वारा स्थायी रूप से समाप्त होना है। तलाक के आधार:

- व्यभिचार

- कूरता
- 2 वर्ष का परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार
- संन्यास
- 7 वर्ष तक जीवित न होने की सूचना

आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B):

- 1 वर्ष से अलग रहना
- दोनों की सहमति

✓ तलाक विवाह को पूर्णतः समाप्त कर देता है। ✓ आपसी सहमति से तलाक अलग प्रावधान है।

✓ 1 वर्ष का अलगाव महत्वपूर्ण है।

Legitimacy of Children Under Section 16 of the Hindu Marriage Act Legitimacy means the legal status of a child born from a valid marriage, giving the child rights in the property of parents.

Section 16 – Legitimacy of Children of Void and Voidable Marriages

Even if a marriage is:

- **Void** (Section 11), or
- **Voidable** (Section 12),

👉 The children born from such marriage are considered **legitimate**.

Important Points

1. Child remains legitimate even if marriage is declared null by court.
2. This provision protects innocent children.
3. Legitimacy applies whether marriage is declared before or after the child's birth.

Property Rights

- ✓ Child can inherit property of **parents only**.
- ✗ Child cannot claim property rights in joint family ancestral property of other relatives (as per earlier interpretation).

Important Case Revanasiddappa v. Mallikarjun

Supreme Court held that children born from void marriages should not suffer and should get rights in parents' property.

संतान की वैधता (धारा 16) यदि विवाहः

- शून्य (Void), या
- शून्यकरणीय (Voidable)

हो, तब भी उससे उत्पन्न संतान वैध (Legitimate) मानी जाएगी।

मुख्य बिंदु

- ✓ संतान निर्दोष है, इसलिए उसके अधिकार सुरक्षित हैं।
- ✓ माता-पिता की संपत्ति में अधिकार है।
- ✗ अन्य रिश्तेदारों की पैतृक संपत्ति में अधिकार सीमित है।

धारा 16 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुधार का प्रावधान है।

Adoption (दत्त ग्रहण) Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act Meaning Adoption means **legally taking a child as one's own child**, giving him/her the same rights as a natural-born child.

Essentials of Valid Adoption

◆ 1. **Capacity of Male Hindu to Adopt (Section 7)**

- Must be major and of sound mind.
- If married, consent of wife is necessary (unless she has renounced the world, converted, or declared of unsound mind).

2. **Capacity of Female Hindu to Adopt (Section 8)**

- Must be major and of sound mind.
- If unmarried, widow, divorced, or husband disqualified, she can adopt.

3. Persons Who May Give in Adoption (Section 9)

- Father
- Mother
- Guardian (with court's permission)

4. Persons Who May Be Adopted (Section 10)

- Must be Hindu
- Must not already be adopted
- Must be unmarried (unless custom permits)
- Must be below 15 years (unless custom permits)

5. Other Conditions (Section 11)

- If adopting a son, adoptive parent must not already have a living son/son's son.
- If adopting a daughter, must not already have a living daughter.
- If male adopts a female child, he must be at least 21 years older than the child (and vice versa).

Effects of Adoption (Section 12)

- ✓ Adopted child is deemed the child of adoptive parents.
- ✓ All rights and duties transfer to adoptive family.
- ✓ Ties with biological family are severed (except marriage restrictions).

Important Case Laxmi Singh v. State of Rajasthan Adoption must be strictly proved; mere claim is not sufficient.

दत्तक ग्रहण दत्तक ग्रहण का अर्थ है किसी बच्चे को विधिक रूप से अपनी संतान बनाना।

आवश्यक शर्तें:

- ✓ दत्तक लेने वाले की क्षमता
 - ✓ दत्तक देने वाले की वैधता
 - ✓ बच्चे की पात्रता
 - ✓ धारा 11 की शर्तों का पालन
-

दत्तक का प्रभाव:

- ✓ बच्चा विधिक संतान माना जाएगा
- ✓ संपत्ति में अधिकार मिलेगा
- ✓ जन्म परिवार से संबंध समाप्त

- 👉 दत्तक लेने के बाद बच्चा प्राकृतिक संतान के समान अधिकार प्राप्त करता है।
- 👉 आवश्यक शर्तों का पालन न होने पर दत्तक अमान्य होगा।

Hindu Minority and Guardianship Act The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 was enacted to **amend and codify the law relating to minority and guardianship among Hindus**. It is supplementary to the Guardians and Wards Act.

1. Application of the Act (Section 2) Applies to:

- Hindus
- Buddhists
- Jains
- Sikhs

2. Meaning of Minor (Section 4) A **minor** is a person who has not completed **18 years of age**.

3. Natural Guardians (Section 6)

(a) For a boy or unmarried girl:

- **Father**, and after him, **Mother**

(b) For illegitimate child:

- **Mother**, and after her, **Father**

(c) For married minor girl:

- **Husband**

👉 However, custody of a child below 5 years is ordinarily with the mother.

4. Powers of Natural Guardian (Section 8)

- Guardian can do acts necessary for benefit of minor.
- Cannot transfer minor's immovable property without court permission.
- Any unauthorized transfer is voidable.

5. Testamentary Guardian (Section 9) A Hindu father or mother may appoint a guardian by will.

6. Welfare of Minor (Section 13)

Welfare of the minor is the paramount consideration. No guardian shall be appointed if it is not in the interest of the minor.

Important Case Githa Hariharan v. Reserve Bank of India

Supreme Court held:

- The word “after” in Section 6 does not mean after the lifetime of father.
- Mother can also act as natural guardian during father’s lifetime if father is absent or indifferent.

हिन्दू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम, 1956 उद्देश्य: अल्पवयस्क (Minor) और अभिभावक (Guardian) संबंधी कानून को संहिताबद्ध करना।

मुख्य प्रावधान

- ✓ 18 वर्ष से कम आयु = अल्पवयस्क
- ✓ पिता प्राकृतिक अभिभावक, उसके बाद माता
- ✓ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः माता को
- ✓ संपत्ति बेचने हेतु न्यायालय की अनुमति आवश्यक
- ✓ बच्चे का हित सर्वोपरि सिद्धांत

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- ☞ Welfare of minor is paramount.
- ☞ माता भी प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है।
- ☞ बिना न्यायालय अनुमति संपत्ति हस्तांतरण अमान्य हो सकता है।

Law of Maintenance Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act The Act codifies the law relating to **maintenance of wife, children, aged parents and dependants** among Hindus.

Meaning of Maintenance (Section 3) “Maintenance” includes:

- Food
- Clothing
- Residence

- Education
- Medical attendance and treatment
- In case of unmarried daughter – reasonable marriage expenses

1. **Maintenance of Wife (Section 18)** A Hindu wife is entitled to be maintained by her husband during her lifetime. She can claim separate residence without losing maintenance if:

- Husband is guilty of cruelty
- Husband deserts her
- Husband has another wife
- Husband converts religion
- Any other justifiable cause

✗ Wife is not entitled if she is unchaste or converts religion.

2. **Maintenance of Widowed Daughter-in-law (Section 19)** She can claim maintenance from her father-in-law if:

- She cannot maintain herself
- She has no property
- Husband's estate is insufficient

3. **Maintenance of Children and Aged Parents (Section 20)**

A Hindu is bound to maintain:

- Legitimate or illegitimate minor children
- Unmarried daughter
- Aged or infirm parents

4. **Maintenance of Dependants (Section 21–22)**

After death of a Hindu, dependants can claim maintenance from his estate.

Dependants include:

- Widow
- Minor children
- Aged parents
- Unmarried daughters

5. Amount of Maintenance (Section 23)

Court considers:

- Position and status of parties
- Reasonable wants of claimant
- Value of property
- Income of both parties

6. Effect of Transfer of Property (Section 25)

If property is transferred to defeat maintenance rights, it can be challenged.

Important Case **Chaturbhuj v. Sita Bai** Court held that maintenance depends on husband's capacity and wife's needs.

भरण-पोषण का कानून (हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956)

भरण-पोषण में शामिल:

- ✓ भोजन
- ✓ वस्त्र
- ✓ आवास
- ✓ शिक्षा
- ✓ चिकित्सा
- ✓ अविवाहित पुत्री के विवाह खर्च

पत्नी का अधिकार (धारा 18) पति जीवनभर पत्नी का भरण-पोषण करेगा।

माता-पिता और संतान (धारा 20)

- ✓ नाबालिग संतान
- ✓ अविवाहित पुत्री
- ✓ वृद्ध माता-पिता

आश्रितों का अधिकार (धारा 21-22) मृतक हिन्दू की संपत्ति से आश्रितों को भरण-पोषण।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- ☞ भरण-पोषण सामाजिक न्याय का प्रावधान है।
- ☞ पत्नी, संतान, माता-पिता को अधिकार।
- ☞ अदालत आय और स्थिति देखकर राशि तय करती है।

Law of Succession under the Hindu Succession Act The Hindu Succession Act, 1956 deals with **inheritance and succession of property among Hindus**.

1. Devolution of Interest in Coparcenary Property (Section 6)

- Originally, only **male coparceners** had rights by birth in Mitakshara coparcenary property.
- After the **2005 Amendment**, **daughters are also coparceners by birth**, equal to sons.
- Daughter has:
 - ✓ Same rights
 - ✓ Same liabilities
 - ✓ Right to demand partition

Important Case: **Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma** Supreme Court held that daughter becomes coparcener **by birth**, whether father is alive or not on 9 Sept 2005.

2. General Rules of Succession in Case of Male Hindu (Section 8)

If a male Hindu dies intestate (without will), property devolves in this order:

✓ Class I Heirs:

- Son
- Daughter
- Widow
- Mother
- Son of predeceased son/daughter, etc.

✓ Class II Heirs:

If no Class I heirs exist, then Class II heirs inherit.

✓ Agnates:

If no Class I & II heirs.

✓ Cognates:

If no agnates.

3. General Rules of Succession in Case of Female Hindu (Section 15) If a female Hindu dies intestate, property devolves:

1. Sons and daughters (including children of predeceased children) and husband
2. Heirs of husband
3. Mother and father
4. Heirs of father
5. Heirs of mother

👉 Property inherited from parents goes back to parental heirs if no children.

4. Testamentary Succession (Section 30) A Hindu may dispose of property by **Will**.

- Applies to separate/self-acquired property.
- After 2005 amendment, coparcenary interest can also be disposed by will.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

♦ धारा 6 – सहभोजी (Coparcenary) संपत्ति

- 2005 संशोधन के बाद पुत्री को पुत्र के समान अधिकार।
- जन्म से सहभोजी का दर्जा।

धारा 8 – पुरुष हिन्दू की मृत्यु पर उत्तराधिकार

- वर्ग I वारिस
- वर्ग II वारिस
- अग्नेट
- कॉग्नेट

धारा 15 – स्त्री हिन्दू की मृत्यु पर उत्तराधिकार

- पुत्र, पुत्री, पति
- पति के वारिस
- माता-पिता
- पिता के वारिस

- माता के वारिस
- **धारा 30 – वसीयत द्वारा उत्तराधिकार** --हिन्दू अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा दे सकता है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- ✓ 2005 संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण।
- ✓ पुत्री = सहभोजी (Coparcener)
- ✓ पुरुष और स्त्री के उत्तराधिकार नियम अलग हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 1. परिचय Hindu Marriage Act हिन्दुओं के विवाह संबंधी कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया। यह 18 मई 1955 से लागू हुआ। यह लागू होता है:

- हिन्दू
- बौद्ध
- जैन
- सिख

2. उद्देश्य

- विवाह कानून का संहिताकरण
- एक विवाह प्रथा (Monogamy)
- तलाक की व्यवस्था
- स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा

3. वैध विवाह की शर्तें (धारा 5)

- किसी पक्ष का जीवित जीवनसाथी न हो
- दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के हों
- वर 21 वर्ष, वधू 18 वर्ष
- निषिद्ध संबंध में न हों
- सपिंड संबंध में न हों

4. विवाह संस्कार (धारा 7)

विवाह प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार होना चाहिए। सप्तपदी को कई मामलों में आवश्यक माना गया है।

5. **दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9)** यदि कोई पक्ष बिना उचित कारण अलग हो जाए।

6. **न्यायिक पृथक्करण (धारा 10)** पति-पत्नी अलग रह सकते हैं, पर विवाह समाप्त नहीं होता।

7. **तलाक (धारा 13)**

आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग (2 वर्ष)
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार
- संन्यास
- मृत्यु की संभावना

हिंदू विधि (Hindu Law) में **मिताक्षरा** और **दायभाग** के बीच का अंतर परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। यहाँ इनका तुलनात्मक विवरण और नोट्स दिए गए हैं:

मिताक्षरा और दायभाग में मुख्य अंतर

आधार	मिताक्षरा (Mitakshara)	दायभाग (Dayabhaga)
रचयिता	इसके रचयिता विज्ञानेश्वर हैं।	इसके रचयिता जीमूतवाहन हैं।
आधार	यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक भाष्य है।	यह कई स्मृतियों का सार (निबंध) है।
क्षेत्र (Region)	यह असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मान्य है।	यह मुख्य रूप से बंगाल और असम में मान्य है।

संपत्ति का अधिकार	पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार जन्म लेते ही मिल जाता है।	पुत्र को अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है।
स्वामित्व	पुत्र पिता के जीवनकाल में भी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकता है।	पिता के जीवित रहते पुत्र बंटवारे की मांग नहीं कर सकता।
उत्तरजीविता का नियम	यहाँ 'उत्तरजीविता का सिद्धांत' (Doctrine of Survivorship) लागू होता है।	यहाँ 'उत्तराधिकार का सिद्धांत' (Doctrine of Inheritance) लागू होता है।
सहदायिकी (Coparcenary)	इसमें केवल पुरुष ही सहदायिकी का हिस्सा होते थे (2005 के संशोधन से पहले)।	इसमें केवल पिता की मृत्यु के बाद ही सहदायिकी बनती है।

1. मिताक्षरा संप्रदाय (Mitakshara School)

- **जन्मजात अधिकार:** इस विचारधारा के अनुसार, एक बालक जैसे ही परिवार में जन्म लेता है, वह अपने पिता, दादा और परदादा की पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार बन जाता है।
- **अविभाजित परिवार:** इसमें परिवार की संपत्ति का हिस्सा तब तक निश्चित नहीं होता जब तक कि बंटवारा (Partition) न हो जाए।
- **शाखाएं:** मिताक्षरा की पांच उप-शाखाएं हैं: बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र (बंबई), द्रविड़ (मद्रास) और पंजाब शाखा।

2. दायभाग संप्रदाय (Dayabhaga School)

- **मृत्यु उपरांत अधिकार:** जब तक पिता जीवित है, वह संपत्ति का पूर्ण स्वामी है। पुत्र का उस पर कोई कानूनी हक नहीं होता।
- **निश्चित हिस्सा:** इसमें प्रत्येक हिस्सेदार का भाग पहले से ही काल्पनिक रूप से निश्चित होता है।
- **स्त्रियों का अधिकार:** इसमें विधवा को संतान न होने पर भी अपने पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिताक्षरा की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिया गया था।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद अब मिताक्षरा और दायभाग के बीच का अंतर काफी कम हो गया है, क्योंकि अब बेटियों को भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में जन्मजात अधिकार (Coparcener) दे दिया गया है।

Custom (रीति-रिवाज) in Hindu Law Custom means a rule of conduct which has been **continuously and uniformly observed for a long time**, and which has obtained the force of law in a particular community, tribe, family, or locality. In Hindu Law, **Custom is an important source of law**. In some cases, a valid custom can even override the written texts (Smriti), if it is ancient and certain.

Definition “Custom is a rule which, having been observed continuously and peacefully for a long time, obtains the force of law.”

Essentials of a Valid Custom For a custom to be legally recognized, it must be:

1. **Ancient** – Followed since time immemorial.
2. **Certain** – Clear and not vague.
3. **Reasonable** – Not opposed to justice, equity, or good conscience.
4. **Continuous** – Followed without interruption.
5. **Not opposed to public policy or statutory law**.

Importance in Hindu Law

- Custom plays a very important role in matters like **marriage, adoption, inheritance, and joint family system**.
- Courts in India have recognized custom as a valid source of Hindu law.
- Under the Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act, certain customs are recognized if they fulfill legal conditions.

Custom is a rule of conduct which has been followed continuously and has acquired the force of law. It is an important source of Hindu law and may override the written law if it is ancient, certain, reasonable, and continuous.” विधि शास्त्र और हिंदू कानून में 'रूढ़ि' या 'प्रथा' (Custom) कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन स्रोत है। [1]

रूढ़ि (Custom) का अर्थ रूढ़ि से तात्पर्य उन नियमों या व्यवहारों से है जो किसी विशेष परिवार, वर्ग या क्षेत्र में बहुत लंबे समय से लगातार चले आ रहे हैं। [1] जब कोई व्यवहार समाज में इतनी गहराई से समा जाता है कि उसे कानून के समान मान्यता मिल जाती है, तो उसे 'रूढ़ि' कहते हैं। [2]

एक वैध रूढ़ि (Valid Custom) की आवश्यक शर्तें कानून की दृष्टि से किसी भी प्रथा को वैध होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है: [2]

1. **प्राचीनता (Antiquity):** प्रथा बहुत पुरानी होनी चाहिए। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसे 'स्मरण शक्ति से परे' (Immemorial) माना जाना चाहिए। [2]
2. **निरंतरता (Continuity):** वह प्रथा बिना किसी रोक-टोक के लगातार चलती आ रही हो। [2]
3. **निश्चितता (Certainty):** प्रथा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। [2]

4. **तार्किकता (Reasonableness):** प्रथा तर्कसंगत होनी चाहिए और न्याय या नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। [2]
5. **लोक नीति के विरुद्ध न हो (Not against Public Policy):** वह राज्य के कानूनों या सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। [2]
6. **अनिवार्यता (Observance as a Right):** लोग उस प्रथा का पालन किसी डर से नहीं, बल्कि अपना अधिकार या कर्तव्य समझकर करते हैं। [1]

रूढ़ियों के प्रकार

- **स्थानीय रूढ़ि (Local Custom):** जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मान्य हो। [1]
- **वर्ग रूढ़ि (Class Custom):** जो किसी विशेष जाति या समुदाय में मान्य हो। [1]
- **पारिवारिक रूढ़ि (Family Custom):** जो केवल एक विशेष परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हो। [1]

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत हिंदू कानून में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है: "एक वैध रूढ़ि लिखित कानून (Text) से अधिक शक्तिशाली होती है।" [1] इसका अर्थ है कि यदि कोई प्राचीन प्रथा किसी पुराने धार्मिक पाठ के विरुद्ध भी है, तो अदालत उस प्रथा को ही मान्यता देगी। **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** के तहत भी कुछ रूढ़ियों को विशेष संरक्षण दिया गया है, जैसे कुछ समुदायों में होने वाले विशिष्ट विवाह संस्कार। [3]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की **धारा 5** के अनुसार, एक वैध विवाह के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें और **सपिण्ड (Sapinda)** संबंधों का निषेध महत्वपूर्ण है।

1. हिंदू विवाह की अनिवार्य शर्तें (धारा 5)

एक विवाह तभी वैध माना जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: [5.1]

- **एकविवाह (Monogamy):** विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए।
- **मानसिक स्वस्थता:** कोई भी पक्ष पागल या गंभीर मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए ताकि वह वैध सहमति दे सके।
- **न्यूनतम आयु:** दूल्हे की आयु **21 वर्ष** और दुल्हन की आयु **18 वर्ष** पूर्ण होनी चाहिए। [5.1]
- **निषिद्ध नातेदारी (Prohibited Relationship):** दोनों पक्ष एक-दूसरे के निषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं होने चाहिए (जब तक कि उनकी रूढ़ि इसकी अनुमति न दे)।
- **सपिण्ड संबंध (Sapinda Relationship):** दोनों पक्ष एक-दूसरे के सपिण्ड नहीं होने चाहिए।

2. सपिण्ड (Sapinda) संबंध क्या है? 'सपिण्ड' का अर्थ है वे लोग जो एक ही 'पिण्ड' (शरीर के अंश या पूर्वज) से जुड़े हों। [5.1]

सपिण्ड की सीमाएँ (धारा 3-f): कानून के अनुसार, आप निम्नलिखित सीमाओं के भीतर विवाह नहीं कर सकते:

1. पिता की ओर से: ऊपर की 5 पीढ़ियों तक।
2. माता की ओर से: ऊपर की 3 पीढ़ियों तक।

गणना में उस व्यक्ति को पहली पीढ़ी माना जाता है जिससे गिनती शुरू होती है। [5.1]

3. निषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ (Degrees of Prohibited Relationship) धारा 3(g) के तहत निम्नलिखित संबंधों में विवाह वर्जित है: [5.1]

- यदि एक दूसरे का वंशज (Descendant) हो (जैसे पिता-पुत्री)।
- यदि एक दूसरे के वंशज की पत्नी या पति रहा हो (जैसे पुत्रवधू या दामाद)।
- भाई-बहन, चाचा-भतीजी, बुआ-भतीजा, या भाई-बहन की संतानें।

अपवाद (Exception) यदि किसी समुदाय या जनजाति की 'रूढ़ि' (Custom) ऐसे विवाह की अनुमति देती है (जैसे दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मामा-भांजी का विवाह), तो वह विवाह धारा 5 के तहत वैध माना जाएगा। [5.1]

उल्लंघन का परिणाम

- **शून्य विवाह (Void Marriage):** यदि सपिण्ड या निषिद्ध नातेदारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विवाह शुरुआत से ही **अमान्य (Zero)** माना जाता है। [5.1]
- **दंड:** धारा 18 के तहत, इन शर्तों को तोड़ने पर जुर्माना या साधारण कारावास की सजा हो सकती है।

full course completed.

*****=====*****

DATE 19.2.26 time 11.30 period 3 Thursday

custom

customs is the tradition that has been practice in society since ancient time from the earliest period custom (aachaar) is regarded as the hights dharm.

Introduction Custom is one of the oldest sources of law. It refers to practices and usages that, through long and consistent observance, acquire the force of law.

According to John Salmond: "Custom is the embodiment of those principles which have commended themselves to the national conscience as principles of justice and public utility."

Essentials of a Valid Custom

1. Antiquity (Ancient Origin)

- The custom must be **ancient**

- It should exist from time immemorial

2. Reasonableness

- The custom must be **reasonable and not arbitrary**
- Unfair or unjust customs are not recognized

3. Certainty

- The custom must be **clear and definite**
- It should not be vague or ambiguous

4. Continuous and Uninterrupted Use

- The custom must be followed **continuously without interruption**

5. Peaceful Enjoyment

- It must be practiced **peacefully without dispute**

6. Conformity with Law and Morality

- The custom must not be **against law or public morality**

7. Compulsory Nature

- The custom must be **binding on the people**
- It should not be optional

8. General Acceptance

- It must be **accepted by the community**

Conclusion Custom becomes law when it is ancient, certain, reasonable, and accepted by society. It plays an important role in shaping legal systems, especially in traditional societies.

रीति-रिवाज के आवश्यक तत्व (Customs) -प्रस्तावना रीति-रिवाज (Custom) कानून का एक प्राचीन स्रोत है। यह उन प्रथाओं को दर्शाता है जो लंबे समय तक निरंतर पालन के कारण कानून का रूप ले लेती हैं। John Salmond के अनुसार:- “रीति-रिवाज उन सिद्धांतों का रूप है जो समाज की अंतरात्मा द्वारा न्याय और उपयोगिता के रूप में स्वीकार किए गए हैं।”

वैध रीति-रिवाज के आवश्यक तत्व

1. प्राचीनता (Antiquity)

- रीति-रिवाज बहुत **पुराना** होना चाहिए

2. युक्तिसंगतता (Reasonableness)

- यह तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए

3. निश्चितता (Certainty)

- यह स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए

4. निरंतरता (Continuous Use)

- इसका पालन लगातार और बिना रुकावट होना चाहिए

5. शांतिपूर्ण पालन (Peaceful Enjoyment)

- इसका पालन बिना विवाद के होना चाहिए

6. कानून और नैतिकता के अनुरूप (Conformity)

- यह कानून और नैतिकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए

7. बाध्यता (Compulsory Nature)

- यह अनिवार्य रूप से पालन किया जाने वाला होना चाहिए

8. सामान्य स्वीकृति (General Acceptance)

- इसे समाज द्वारा स्वीकार किया गया होना चाहिए

निष्कर्ष - रीति-रिवाज तभी कानून बनते हैं जब वे प्राचीन, निश्चित, युक्तिसंगत और समाज द्वारा स्वीकार किए गए हों। यह कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

case for custom LUXMI V BHAGWANT BUVA 2013

in this case the hon'ble s.c. stated that a customs became legally enforceable when the majority of people make the continues use of such practice.

Meaning of "Onus" (Law Term) Onus means a **burden or responsibility**.

👉 In law, it refers to the **burden of proof**, i.e., the duty placed on a party to prove a fact in a case.

Example

- In criminal cases, the **onus is on the prosecution** to prove the guilt of the accused.

Onus (ओनुस) का अर्थ है भार या जिम्मेदारी। 👉 विधि में इसका अर्थ होता है **प्रमाण का भार (Burden of Proof)**, अर्थात किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी।

उदाहरण

- आपराधिक मामलों में **अभियोजन (prosecution)** पर यह भार होता है कि वह आरोपी का दोष सिद्ध करे।

- When a custom has attained **judicial recognition**, no further proof is required. However, in cases where a customary practice has not received judicial recognition, the **burden of proof lies on the person who alleges the existence of such a custom.**
- ---

- जब किसी रीति-रिवाज को **न्यायिक मान्यता (judicial recognition)** प्राप्त हो जाती है, तब उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जिन मामलों में किसी प्रथा को न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, वहाँ उस प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध करने का **भार उसी व्यक्ति पर होता है जो उसका दावा करता है।**

CASE MUNNA LAL V RAJ KUMAR 1972---- case for custom

MODERN SOURCES OF LAW Modern sources of law refer to those sources from which law is derived in present-day legal systems. Unlike ancient sources (customs, religion), modern law is mainly created and recognized by the State.

1. Legislation (Statutory Law)

- It is the **most important modern source of law**
- Law is made by the **legislature (Parliament/State Legislature)**
- It is **written and codified**

👉 Example: Acts passed by Parliament

2. Precedent (Judicial Decisions)

- Law developed through **decisions of courts**
- Based on the principle of **stare decisis** (to follow previous decisions)

👉 Important in countries like India and England

3. Custom

- Though ancient, it is still recognized as a **modern source** when accepted by courts
- Must be **reasonable and certain**

4. Juristic Writings

- Opinions of legal scholars and jurists
- Used as a **persuasive source** in courts

👉 Example: Writings of John Salmond

5. Equity

- Based on **principles of fairness, justice, and good conscience**
- Applied when strict law is inadequate

Conclusion

Modern sources of law ensure that law is **systematic, certain, and adaptable**. Among them, legislation and precedent play the most important role in the present legal system.

आधुनिक विधि के स्रोत (Modern Sources of Law) – आधुनिक विधि के स्रोत वे माध्यम हैं जिनसे वर्तमान समय में कानून का निर्माण और विकास होता है। प्राचीन स्रोतों के विपरीत, आधुनिक कानून मुख्यतः राज्य द्वारा निर्मित और मान्यता प्राप्त होते हैं।

1. विधायन (Legislation)

- यह आधुनिक कानून का **सबसे महत्वपूर्ण स्रोत** है
- संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है
- यह लिखित और **संहिताबद्ध (codified)** होता है

2. न्यायिक दृष्टांत (Precedent)

- न्यायालयों के निर्णयों से कानून का विकास
- “**stare decisis**” सिद्धांत पर आधारित

3. प्रथा (Custom)

- प्राचीन होने के बावजूद आज भी मान्य है
- न्यायालय द्वारा स्वीकार होने पर लागू होती है

4. विधिवेत्ताओं के लेख (Juristic Writings)

- विद्वान न्यायशास्त्रियों के विचार
- न्यायालय में सहायक (persuasive) स्रोत

👉 उदाहरण: John Salmond

5. न्यायसंगतता (Equity)

- न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना पर आधारित
- जहाँ सख्त कानून अपर्याप्त हो

निष्कर्ष – आधुनिक विधि के स्रोत कानून को संगठित, निश्चित और लचीला बनाते हैं। इनमें विधायन और न्यायिक दृष्टांत सबसे महत्वपूर्ण हैं।

Some important legislative Acts relating to social reforms in India are:

1. **Caste Disabilities Removal Act, 1850** This Act removed disabilities arising out of change of religion or caste. A person would not lose property rights merely by converting to another religion.
2. **Hindu Widows' Remarriage Act, 1856** This Act legalized the remarriage of Hindu widows and aimed to improve their social condition.
3. **Hindu Wills Act, 1870** This Act provided rules regarding the making of wills by Hindus, especially in certain territories.

4. **Special Marriage Act, 1872** This Act allowed **inter-caste and inter-religious marriages** without requiring conversion, promoting social reform and equality.

भारत में सामाजिक सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं:

1. **Caste Disabilities Removal Act, 1850** इस अधिनियम ने धर्म या जाति परिवर्तन के कारण होने वाली अयोग्यताओं को समाप्त किया। किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
2. **Hindu Widows' Remarriage Act, 1856** इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया।
3. **Hindu Wills Act, 1870** इस अधिनियम में हिंदुओं द्वारा वसीयत (Will) बनाने के नियम निर्धारित किए गए।
4. **Special Marriage Act, 1872** इस अधिनियम ने **अंतरजातीय (inter-caste) और अंतरधार्मिक (inter-religious) विवाह** को संभव बनाया, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला।

Modern Legislation In 1944, a Hindu Law Committee was constituted under the chairmanship of B. N. Rau (Sir B. N. Rau). A draft Hindu Code was prepared in 1948, which later resulted in the enactment of four major Acts:

- a) **Hindu Marriage Act, 1955**
- b) **Hindu Succession Act, 1956**
- c) **Hindu Minority and Guardianship Act, 1956**
- d) **Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956**

These Acts collectively reformed and codified Hindu personal laws in modern India.

आधुनिक विधायन (Modern Legislation) - सन् 1944 में B. N. Rau (सर बी. एन. राव) की अध्यक्षता में हिंदू विधि समिति का गठन किया गया। सन् 1948 में एक प्रारूप (Draft) हिंदू कोड तैयार किया गया, जिसके आधार पर बाद में चार प्रमुख अधिनियम पारित किए गए:

- a) **Hindu Marriage Act, 1955**
- b) **Hindu Succession Act, 1956**
- c) **Hindu Minority and Guardianship Act, 1956**
- d) **Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956**

इन अधिनियमों ने आधुनिक भारत में हिंदू व्यक्तिगत विधि को संशोधित और संहिताबद्ध किया।

Justice, Equity and Good Conscience Justice, equity, and good conscience are regarded as an important source of law. In cases where there is a conflict between two sources of law, and no clear rule is available, the courts apply the principles of **justice, equity, and good conscience** to decide the matter. These principles ensure fairness, reasonableness, and moral justice in legal decisions.

न्याय, समानता और सद्बिबेक (Justice, Equity and Good Conscience) न्याय, समानता और सद्बिबेक को विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जब दो विधिक स्रोतों के बीच संघर्ष होता है और कोई स्पष्ट नियम उपलब्ध नहीं होता, तब न्यायालय **न्याय, समानता और सद्बिबेक** के सिद्धांतों को लागू करके निर्णय देता है। ये सिद्धांत न्याय, उचितता और नैतिकता को सुनिश्चित करते हैं।

case Gurunath v. Kanta Bai The Hon'ble Supreme Court held that in the absence of any existing law on the subject, the court shall apply the principles of **justice, equity, and good conscience** to decide the case.

Gurunath v. Kanta Bai माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब किसी विषय पर कोई विद्यमान कानून उपलब्ध नहीं हो, तब न्यायालय **न्याय, समानता और सद्बिबेक (justice, equity and good conscience)** के सिद्धांतों को लागू करके निर्णय करेगा।

Kenchava v. Girimallappa In this case, the Privy Council held that a **murderer is disqualified from inheriting the property of the victim**. This decision was based on the principles of **justice, equity, and good conscience**, ensuring that a person should not benefit from his own wrongful act.

Kenchava v. Girimallappa इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि **हत्यारा अपने ही पीड़ित की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता**। यह निर्णय **न्याय, समानता और सद्बिबेक** के सिद्धांतों पर आधारित था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि कोई व्यक्ति अपने गलत कार्य का लाभ न उठा सके।

*****=====*****

date 12-3-2026 time 11.30 am period 3 Thursday

section 5 condition for hindu marriage act 1955

case yammuna bai v anand rao 1988 -

Sarla Mudgal v u o l --

lily thomas v u o i

prohibited relationship father side 5 upside and mother side 3 upside step.

Full and Half Uterine Relationship

1. Full Uterine Relationship A **full uterine relationship** exists when two persons are born of the **same mother**. 🖐️ Example: Brother and sister born from the same mother are called **uterine siblings**.

2. Half Uterine Relationship A **half uterine relationship** exists when two persons have the **same mother but different fathers**. 🖐️ Example: Two children of the same mother but from different fathers are called **half uterine siblings**.

Note

- **Uterine** → related through **mother**

- Full uterine = same mother
- Half uterine = same mother, different father

Full & Half Uterine Relationship

1. **पूर्ण गर्भ संबंध (Full Uterine Relationship)** जब दो व्यक्तियों की माता एक ही होती है, तो इसे पूर्ण गर्भ संबंध कहते हैं। 🖱 उदाहरण: एक ही माँ से जन्मे भाई-बहन
2. **अर्ध गर्भ संबंध (Half Uterine Relationship)** जब दो व्यक्तियों की माता एक ही हो लेकिन पिता अलग-अलग हों, तो इसे अर्ध गर्भ संबंध कहते हैं। 🖱 उदाहरण: एक ही माँ से लेकिन अलग-अलग पिता से जन्मे बच्चे

Legitimate and Illegitimate Relationship

1. **Legitimate Relationship** A legitimate relationship is one where a child is born **within a lawful marriage**. 🖱 Such a child is called a **legitimate child** and has **full legal rights**, including inheritance rights.
2. **Illegitimate Relationship** An illegitimate relationship is one where a child is born **outside a lawful marriage**. 🖱 Such a child is called an **illegitimate child**. Traditionally, such children had limited legal rights, especially in matters of inheritance, though modern laws have improved their rights.

Key Difference

Basis	Legitimate	Illegitimate
Birth	Within lawful marriage	Outside marriage
Legal Status	Fully recognized	Limited recognition (earlier)
Rights	Full rights	Restricted (but improving)

(Legitimate & Illegitimate Relationship)

1. **वैध संबंध (Legitimate Relationship)** जब कोई बच्चा कानूनी विवाह के अंदर जन्म लेता है, तो उसे वैध संबंध कहा जाता है। 🖱 ऐसे बच्चे को **वैध संतान** कहा जाता है और उसे **संपूर्ण कानूनी अधिकार**, जैसे संपत्ति में अधिकार, प्राप्त होते हैं।
2. **अवैध संबंध (Illegitimate Relationship)** जब कोई बच्चा कानूनी विवाह के बाहर जन्म लेता है, तो उसे अवैध संबंध कहा जाता है। 🖱 ऐसे बच्चे को **अवैध संतान** कहा जाता है। पहले इनके अधिकार सीमित थे, लेकिन आधुनिक कानूनों में इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं।

मुख्य अंतर

आधार वैध अवैध

जन्म विवाह के अंदर विवाह के बाहर

स्थिति पूर्ण मान्यता सीमित (पहले), अब सुधार

अधिकार पूर्ण अधिकार सीमित, पर अब बढ़ रहे

Blood Relationship and Adoption Relationship

1. Blood Relationship A **blood relationship** refers to a relationship that exists **by birth**. It arises when persons are biologically related to each other. 🖱 Example: Relationship between parents and children, brothers and sisters.

2. Adoption Relationship An **adoption relationship** is a legal relationship created **by law**, not by birth. When a child is legally adopted, he/she is treated as the **natural child of the adoptive parents**.

🖱 Example: An adopted child has the same rights as a biological child.

Key Difference

Basis **Blood Relationship** **Adoption Relationship**

Origin By birth By law (adoption)

Nature Natural Legal

Rights Automatic Given after adoption

Example Parents & children Adopted child & parents

Important Point Under **Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956**, an adopted child is treated as equal to a natural child in most legal matters.

(Blood & Adoption Relationship)

1. रक्त संबंध (Blood Relationship) रक्त संबंध वह संबंध है जो **जन्म से उत्पन्न होता है**। इसमें व्यक्ति आपस में जैविक रूप से जुड़े होते हैं। 🖱 उदाहरण: माता-पिता और संतान, भाई-बहन

2. दत्तक संबंध (Adoption Relationship) दत्तक संबंध वह है जो **कानून द्वारा बनाया जाता है**, जन्म से नहीं। जब किसी बच्चे को विधिक रूप से गोद लिया जाता है, तो वह दत्तक माता-पिता की संतान माना जाता है।

🖱 उदाहरण: गोद लिया गया बच्चा

मुख्य अंतर

आधार रक्त संबंध दत्तक संबंध

आधार जन्म से कानून से

प्रकृति प्राकृतिक विधिक

अधिकार स्वतः गोद लेने के बाद

उदाहरण माता-पिता दत्तक माता-पिता

महत्वपूर्ण बिंदु - Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 के अनुसार, दत्तक संतान को प्राकृतिक संतान के समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

*****=====*****

17-03-2026 time 11.30 am Tuesday period 3

Types of Hindu Marriage Ancient Hindu law recognized **eight forms of marriage**, classified into approved and unapproved forms.

(A) Approved Forms of Marriage

1. Brahma Marriage

- The father gives his daughter to a learned and worthy man
- Considered the **best form of marriage**

2. Daiva Marriage

- The daughter is given to a priest who performs a sacrifice
- Religious in nature

3. Arsha Marriage

- Marriage in exchange for symbolic gifts (like cows)
- Simple and traditional

4. Prajapatya Marriage

- Marriage performed with blessings and duties of husband and wife
- Focus on **dharma (duty)**

(B) Unapproved Forms of Marriage

5. Gandharva Marriage

- Marriage by **mutual consent** (love marriage)
- No rituals required

6. Asura Marriage

- Marriage by **payment of money** to bride's family
- Considered improper

7. Rakshasa Marriage

- Marriage by **force or abduction**
- Practiced in ancient warrior culture

8. Paisacha Marriage

- Marriage by **fraud or misconduct** (e.g., taking advantage of a woman without consent)
- Considered the **worst form**

Conclusion Out of these, the first four are approved, while the last four are disapproved. Modern Hindu law does not recognize these forms but emphasizes **consent and legality**.

हिंदू विवाह के प्रकार (Types of Marriage) – प्राचीन हिंदू विधि में विवाह के **आठ प्रकार** माने गए हैं, जिन्हें स्वीकृत (approved) और अस्वीकृत (unapproved) में बाँटा गया है।

(A) स्वीकृत विवाह (Approved Forms)

1. ब्रह्म विवाह (Brahma Marriage)

- पिता अपनी पुत्री को योग्य वर को देता है
- सबसे श्रेष्ठ विवाह

2. दैव विवाह (Daiva Marriage)

- यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या दी जाती है
- धार्मिक स्वरूप

3. आर्ष विवाह (Arsha Marriage)

- प्रतीकात्मक उपहार (जैसे गाय) के बदले विवाह
- सरल विवाह

4. प्राजापत्य विवाह (Prajapatya Marriage)

- कर्तव्यों और धर्म पर आधारित विवाह
- पति-पत्नी के कर्तव्य पर जोर

(B) अस्वीकृत विवाह (Unapproved Forms)

5. गंधर्व विवाह (Gandharva Marriage)

- आपसी सहमति से विवाह (प्रेम विवाह)

6. असुर विवाह (Asura Marriage)

- धन देकर विवाह
- अनुचित माना जाता है

7. राक्षस विवाह (Rakshasa Marriage)

- बलपूर्वक या अपहरण द्वारा विवाह

8. पैशाच विवाह (Paisacha Marriage)

- धोखे या अनैतिक तरीके से विवाह
- सबसे निकृष्ट प्रकार

निष्कर्ष पहले चार विवाह मान्य थे, जबकि अंतिम चार अमान्य माने गए। आधुनिक कानून में इनका महत्व कम है और अब **सहमति व वैधता** को प्राथमिकता दी जाती है।

registration of hindu marriage is not mandatory. case SEEMA V ASHWANI KUMAR 2006

Gullipulli Sowria v. Bandaru Pavani In this case, the Supreme Court dealt with the validity of marriage under Hindu law. The Court held that **a marriage between a Hindu male and a Christian female is not valid under the Hindu Marriage Act unless the non-Hindu partner converts to Hinduism**. Therefore, for a valid Hindu marriage, both parties must be Hindus at the time of marriage.

Gullipulli Sowria v. Bandaru Pavani इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की वैधता पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि **यदि एक पक्ष हिंदू है और दूसरा गैर-हिंदू (जैसे ईसाई) है, तो बिना धर्म परिवर्तन के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह वैध नहीं माना जाएगा।** इसलिए वैध हिंदू विवाह के लिए दोनों पक्षों का हिंदू होना आवश्यक है।

Special Marriage Act – Inter-Religious Marriage A marriage between a Christian man and a Hindu woman is **not valid under the Hindu Marriage Act, 1955**, because the Act applies only when **both parties are Hindus**.

☝ Such inter-religious marriages can be validly solemnized under the **Special Marriage Act, 1954**, which provides a legal framework for marriages between persons of different religions without requiring conversion.

Case Law V. D. Rahatkhan v. T. Prasanth In this case, the court held that where parties belong to different religions, their marriage cannot be governed by the Hindu Marriage Act unless both are Hindus. Such marriages must be performed under the Special Marriage Act to be legally valid.

विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) एक ईसाई पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** के अंतर्गत वैध नहीं होता, क्योंकि यह अधिनियम केवल तब लागू होता है जब **दोनों पक्ष हिंदू**

हों। 🖐️ ऐसे अंतर-धार्मिक विवाह **Special Marriage Act, 1954** के अंतर्गत वैध रूप से किए जा सकते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती।

प्रमुख मामला (Case Law) V. D. Rahatkhan v. T. Prasanth इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जब दोनों पक्ष अलग-अलग धर्म के हों, तो उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। ऐसे विवाह को वैध बनाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक है।

V.D. Bhanot v. Savita Bhanot Vishakha judgement 2005 (THIS CASE SHOW THAT VISHAKA JUDGEMENT LAW APPLY AS Retrospective Law)

🔑 **Key Issue** Whether a woman can claim protection under the **Protection of Women from Domestic Violence Act** for acts that happened **before the Act came into force (2005)**.

⚖️ **Judgment (Held)** The Supreme Court of India held:

- Yes, a woman **can file a complaint even for past acts of domestic violence**.
- The Act has a **retrospective effect to some extent**.
- If the woman is still in a domestic relationship or suffering consequences, she can seek relief.

🧠 **Important Principle**

- The law is **beneficial legislation**, meant to protect women.
- Therefore, it should be **interpreted liberally** in favor of victims.

क्या Protection of Women from Domestic Violence Act के अंतर्गत महिला पुराने (2005 से पहले के) घरेलू हिंसा के मामलों में भी राहत प्राप्त कर सकती है?

⚖️ **निर्णय (Judgment)** Supreme Court of India ने यह निर्णय दिया कि:

- महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत **पुराने घटनाओं (past acts)** के लिए भी शिकायत कर सकती है।
- यह अधिनियम **आंशिक रूप से पूर्वव्यापी (retrospective)** प्रभाव रखता है।
- यदि महिला अभी भी उस संबंध के प्रभाव में है या उसके परिणाम भुगत रही है, तो उसे **कानूनी सुरक्षा और राहत** मिलेगी।

🧠 **मुख्य सिद्धांत (Principle)**

- यह कानून एक **कल्याणकारी (beneficial) कानून** है।
- इसलिए इसकी **व्याख्या उदारतापूर्वक (liberal interpretation)** की जानी चाहिए ताकि पीड़ित महिला को अधिकतम संरक्षण मिल सके।

✦ महत्व (Importance for Exams)

- यह केस स्पष्ट करता है कि Domestic Violence Act का प्रभाव केवल भविष्य तक सीमित नहीं है।
- महिलाओं को अतीत की हिंसा के लिए भी न्याय पाने का अधिकार देता है।
- यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है।

👉 **निष्कर्ष** इस निर्णय से यह स्थापित होता है कि घरेलू हिंसा कानून का उद्देश्य केवल वर्तमान नहीं बल्कि भूतकाल में हुई अन्यायपूर्ण घटनाओं का भी समाधान करना है, जिससे महिलाओं को व्यापक न्याय मिल सके।

Void Marriage – Section 11 (Hindu Marriage Act, 1955) A void marriage is no marriage in the eyes of law. It is treated as if it **never existed from the beginning**. According to **Section 11**, any marriage solemnized after the commencement of the Act shall be **null and void**, and may, on a petition presented by either party, be so declared by a **decree of nullity** if it contravenes any of the conditions specified in **Section 5 clauses (i), (iv), and (v)**.

Conditions under Section 5 (Relevant Clauses) A marriage becomes void if it violates:

- **Section 5(i)** – Either party has a **living spouse** at the time of marriage (bigamy).
- **Section 5(iv)** – Parties are within **prohibited degrees of relationship**, unless custom permits.
- **Section 5(v)** – Parties are **sapindas of each other**, unless allowed by custom.

Key Features of Void Marriage

- It is **invalid from the very beginning (void ab initio)**.
- No legal rights or obligations arise from such marriage.
- A decree of nullity is **not mandatory**, but may be obtained for legal clarity.

Voidable Marriage (Brief Note) A voidable marriage is **valid until it is annulled by a court**. It remains legally binding unless one party files a petition to declare it void. (Examples: lack of consent, fraud, impotence, etc. under Section 12)

शून्य विवाह – धारा 11 (Hindu Marriage Act, 1955) शून्य विवाह (Void Marriage) वह विवाह है जो कानून की नजर में **विवाह है ही नहीं**। इसे ऐसा माना जाता है मानो यह आरंभ से कभी अस्तित्व में ही नहीं था। धारा 11 के अनुसार, अधिनियम के लागू होने के बाद संपन्न कोई भी विवाह **शून्य (null and void)** होगा, और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय इसे **शून्यता की डिक्री (decree of nullity)** द्वारा घोषित कर सकता है, यदि वह धारा 5 की शर्तों (clause (i), (iv), (v)) का उल्लंघन करता है।

धारा 5 की संबंधित शर्तें विवाह शून्य होगा यदि:

- धारा 5(i) – विवाह के समय किसी एक पक्ष का **जीवित पति या पत्नी मौजूद हो** (द्विविवाह)।
- धारा 5(iv) – पक्षकार **निषिद्ध संबंधों (prohibited degrees)** में आते हों, जब तक कि प्रथा इसकी अनुमति न दे।

- धारा 5(v) – पक्षकार सपिंड संबंध (sapinda relationship) में हों, जब तक कि प्रथा अनुमति न दे।

शून्य विवाह की विशेषताएँ

- यह विवाह आरंभ से ही अमान्य (void ab initio) होता है।
- इससे कोई वैधानिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते।
- न्यायालय की डिक्री आवश्यक नहीं है, परंतु कानूनी स्पष्टता के लिए ली जा सकती है।

शून्यकरणीय विवाह (Voidable Marriage) - शून्यकरणीय विवाह वह होता है जो तब तक वैध रहता है जब तक न्यायालय उसे निरस्त (annul) न कर दे।

- यह विवाह प्रारंभ में वैध माना जाता है।
- इसे केवल पीड़ित पक्ष द्वारा याचिका दायर करके ही शून्य घोषित कराया जा सकता है।
- उदाहरण: सहमति का अभाव, धोखा (fraud), नपुंसकता (impotency) आदि (धारा 12)।

निष्कर्ष इस प्रकार, शून्य विवाह पूर्णतः अमान्य होता है, जबकि शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध रहता है जब तक न्यायालय उसे निरस्त न कर दे।

*****=====*****=====*****=====*****=====

date 20.3.26 time 1130 am period 3 Friday

Meaning Restitution of Conjugal Rights means the restoration of marital rights and cohabitation between husband and wife.

Provision – Section 9, Hindu Marriage Act, 1955

If either the husband or the wife has **withdrawn from the society of the other without reasonable excuse**, the aggrieved party may file a petition in the court for **restitution of conjugal rights**.

The court, if satisfied that:

- the statements are true, and
- there is no legal ground to refuse relief,

may pass a **decree for restitution of conjugal rights**.

Essential Conditions

1. One party has **withdrawn from the society** of the other.
2. The withdrawal is **without reasonable excuse**.
3. The aggrieved party files a **petition before the court**.

Effect of Decree

- The court orders the defaulting spouse to **resume cohabitation**.

- If not complied with, it may become a **ground for divorce**.

Important Case Law

- Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha
👉 The Supreme Court upheld the **constitutional validity** of Section 9.

Conclusion Section 9 aims to **preserve marriage** and promote reconciliation between spouses.

अर्थ दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) का अर्थ है पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध और साथ रहने के अधिकार को पुनः स्थापित करना।

प्रावधान - धारा 9, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 यदि पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर कर सकता है।

यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि:

- याचिका में दिए गए तथ्य सही हैं, और
- राहत देने से रोकने वाला कोई कानूनी आधार नहीं है,

तो न्यायालय दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित कर सकता है।

आवश्यक तत्व

1. एक पक्ष ने दूसरे का साथ छोड़ दिया हो।
2. यह त्याग बिना उचित कारण के हो।
3. पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में याचिका दायर की हो।

डिक्री का प्रभाव

- न्यायालय दोषी पक्ष को साथ रहने (cohabitation) का आदेश देता है।
- आदेश का पालन न करने पर यह तलाक का आधार बन सकता है।

महत्वपूर्ण वाद (Case Law)

- Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha 👉 इस मामले में धारा 9 की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया गया।

निष्कर्ष धारा 9 का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना और पति-पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

Restitution of Conjugal Rights – Section 9 When either the husband or the wife, **without reasonable excuse**, withdraws from the society of the other, the aggrieved party may file a **petition before the District Court** for restitution of conjugal rights.

If the court is satisfied that:

- the statements made in the petition are **true**, and
- there is **no legal ground** why the application should not be granted,

the court may pass a **decree for restitution of conjugal rights**.

The expression “**withdrawal from society**” is not limited to physical separation alone; it may also include **mental separation**. It signifies a withdrawal from the **totality of the marital relationship**, including companionship, cohabitation, and mutual obligations.

दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना - धारा 9 जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है। यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो कि:

- याचिका में दिए गए कथन **सत्य हैं**, और
- याचिका अस्वीकार करने का कोई **कानूनी आधार नहीं है**,

तो न्यायालय दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित कर सकता है। “**समाज से अलग होना (withdrawal from society)**” केवल शारीरिक अलगाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें **मानसिक अलगाव** भी शामिल हो सकता है। इसका अर्थ है वैवाहिक संबंधों की **समग्रता से अलग होना**, जैसे साथ रहना, भावनात्मक संबंध और वैवाहिक कर्तव्यों का त्याग।

Restitution of Conjugal Rights – Polished Burden of Proof The **burden of proving “reasonable excuse”** lies on the person who has **withdrawn from the society** of the other spouse.

Decree of Restitution of Conjugal Rights A decree for restitution of conjugal rights is enforced in accordance with **Order XXI Rule 32 of the Code of Civil Procedure (CPC)**.

Before granting such a decree, the following conditions must be fulfilled:

- (a) The respondent (other spouse) has **withdrawn from the society** of the petitioner.
- (b) There is **no reasonable excuse** for such withdrawal.
- (c) The court is **satisfied about the truth** of the statements made in the petition.
- (d) There is **no legal ground** for refusing the decree.

दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना - साबित करने का भार (Burden of Proof) उचित कारण (reasonable excuse) सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसने दूसरे जीवनसाथी का साथ छोड़ दिया है।

दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन **सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 32** के अंतर्गत कराया जाता है। इस डिक्री को पारित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

- (क) प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता का साथ छोड़ दिया हो।
- (ख) ऐसा छोड़ना बिना उचित कारण के हो।

(ग) न्यायालय याचिका में दिए गए कथनों की सत्यता से संतुष्ट हो।

(घ) डिक्री देने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार न हो।

Effect of Non-Compliance of Decree of Restitution of Conjugal Rights When a decree for restitution of conjugal rights is not complied with, the law provides certain consequences:

(a) **Enforcement of Decree** Under **Order XXI Rule 32 of the Code of Civil Procedure (CPC)**, if the party against whom the decree is passed **wilfully disobeys** it, the decree may be enforced by **attachment of property**.

(b) **Ground for Divorce** If there is **no resumption of cohabitation** even after **one year** from the date of the decree, it becomes a **ground for divorce** under **Section 13(1A)(ii) of the Hindu Marriage Act, 1955**.

Constitutional Validity of Section 9

1. **T. Sareetha v. T. Venkata Subbaiah** The court declared **Section 9 unconstitutional**, holding that it violated **Article 14 and Article 21** of the Constitution.

2. **Harvinder Kaur v. Harmander Singh** The court **upheld the constitutional validity** of Section 9.

3. **Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha** The Supreme Court of India upheld Section 9 and held that it **does not violate Article 21**, as it serves a **social purpose of preventing the breakdown of marriage**.

4. **Reena Kumari v. Dinesh Kumar Mahto** The Court held that a wife is **entitled to maintenance under Section 125 CrPC**, even if she refuses to live with her husband due to **ill-treatment**, despite a decree for restitution of conjugal rights.

Conclusion Non-compliance with a decree may lead to **property attachment** and also become a **ground for divorce**, while judicial decisions have clarified its **constitutional validity and practical limitations**.

दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन न करने के प्रभाव जब दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन नहीं किया जाता, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

(क) **डिक्री का प्रवर्तन (Enforcement)** सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 32 के अनुसार, यदि जिस पक्ष के विरुद्ध डिक्री पारित हुई है वह **जानबूझकर उसका पालन नहीं करता**, तो डिक्री का पालन **संपत्ति की कुर्की (attachment of property)** द्वारा कराया जा सकता है।

(ख) **तलाक का आधार (Ground for Divorce)** यदि डिक्री के बाद **एक वर्ष तक सहवास (cohabitation) पुनः स्थापित नहीं होता**, तो यह **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1A)(ii) के अंतर्गत तलाक का आधार बन जाता है**।

धारा 9 की संवैधानिक वैधता

1. **T. Sareetha v. T. Venkata Subbaiah** इस मामले में न्यायालय ने धारा 9 को **अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया**।

2. **Harvinder Kaur v. Harmander Singh** इस मामले में न्यायालय ने धारा 9 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया।

3. **Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha** Supreme Court of India ने धारा 9 को वैध ठहराते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि इसका उद्देश्य विवाह को टूटने से बचाना है।

4. **Reena Kumari v. Dinesh Kumar Mahto** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को धारा 125 CrPC के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार है, भले ही वह पति के साथ रहने से इंकार करे, यदि पति द्वारा दुर्व्यवहार (ill-treatment) किया गया हो।

निष्कर्ष डिक्री का पालन न करने पर संपत्ति की कुर्की हो सकती है और यह तलाक का आधार भी बन सकता है, जबकि न्यायालयों ने इसकी संवैधानिक वैधता और सीमाओं को स्पष्ट किया है।

=====*****=====*****=====*****

date 24-3-26 period 3 time 11.30 am Tuesday

Judicial Separation – Section 10 (Hindu Marriage Act, 1955) Judicial Separation is a legal remedy less severe than divorce. Under this, the marital tie is **not dissolved**, but the husband and wife are relieved from the obligation to live together and perform matrimonial duties.

- It provides an opportunity for **reconciliation**.
- If there is **no resumption of cohabitation for one year or more**, it becomes a **ground for divorce** under Section 13(1A).

Divorce – Meaning The term “**divorce**” is derived from the Latin word *divortium*, which means to separate. In legal terms, divorce means the **dissolution of the matrimonial bond**, i.e., complete termination of the marriage.

Provisions Relating to Divorce The provisions relating to divorce under the **Hindu Marriage Act, 1955** are contained in:

- **Section 13** – Grounds for divorce
- **Section 13(1A)** – Divorce after judicial separation or restitution decree
- **Section 13A** – Alternative relief in divorce proceedings
- **Section 13B** – Divorce by mutual consent
- **Section 14** – No petition for divorce within one year of marriage (with exceptions)
- **Section 15** – When divorced persons may remarry

Conclusion Judicial separation is a **temporary relief**, while divorce is a **permanent dissolution of marriage**. The law provides both remedies to balance **reconciliation and final separation**.

न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक – न्यायिक पृथक्करण – धारा 10 (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955)

न्यायिक पृथक्करण तलाक की तुलना में कम कठोर (less severe) उपाय है। इसमें विवाह समाप्त नहीं होता, बल्कि पति-पत्नी को एक साथ रहने और वैवाहिक कर्तव्यों के पालन से मुक्त कर दिया जाता है।

- यह पति-पत्नी को सुलह (reconciliation) का अवसर देता है।
- यदि एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास पुनः स्थापित नहीं होता, तो यह धारा 13(1A) के अंतर्गत तलाक का आधार बन जाता है।

तलाक - अर्थ "Divorce" शब्द लैटिन शब्द *divortium* से लिया गया है, जिसका अर्थ है **अलग होना**। कानूनी रूप में, तलाक का अर्थ है वैवाहिक संबंध का पूर्णतः समाप्त होना।

तलाक से संबंधित प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में तलाक से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित धाराओं में दिए गए हैं:

- धारा 13 – तलाक के आधार
- धारा 13(1A) – न्यायिक पृथक्करण या दांपत्य अधिकारों की डिक्री के बाद तलाक
- धारा 13A – वैकल्पिक राहत
- धारा 13B – पारस्परिक सहमति से तलाक
- धारा 14 – विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक याचिका पर रोक (कुछ अपवादों सहित)
- धारा 15 – तलाक के बाद पुनर्विवाह

Meaning of Adultery Adultery means **voluntary sexual intercourse of a married person with someone other than his or her spouse.**

Under matrimonial law, adultery is a **ground for divorce** under **Section 13(1)(i) of the Hindu Marriage Act, 1955.**

Adultery as a Ground for Divorce A spouse can seek divorce if the other spouse has:

- Engaged in **voluntary sexual relations** outside marriage.
- The act must be **proved** (usually through circumstantial evidence, not direct proof).

Important Case **Joseph Shine v. Union of India**

Facts

- Section 497 of the Indian Penal Code made adultery a **criminal offence**.
- It punished only the **man**, not the woman, and treated the woman as the **property of the husband**.

Judgment The Supreme Court of India held:

- **Section 497 IPC is unconstitutional.**

- It violates **Article 14 (Equality)** and **Article 21 (Right to Life and Personal Liberty)**.
- It is based on **patriarchal notions**.

Key Observations

- Adultery is **no longer a crime** in India.
- However, it remains a **civil wrong** and a **valid ground for divorce**.
- Marriage does not mean **ownership or control over a spouse**.

Conclusion After this judgment, adultery is treated as a **private matrimonial issue**, not a criminal offence, but it still plays an important role in **divorce proceedings**.

व्यभिचार (Adultery) का अर्थ व्यभिचार का अर्थ है कि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ **स्वेच्छा से यौन संबंध स्थापित करे**। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की **धारा 13(1)(i)** के अंतर्गत यह **तलाक का एक आधार** है।

तलाक के आधार के रूप में व्यभिचार यदि पति या पत्नी:

- विवाह के बाहर **यौन संबंध बनाता/बनाती है**,
- और यह तथ्य **साबित हो जाता है**,

तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है।

महत्वपूर्ण वाद Joseph Shine v. Union of India

तथ्य (Facts)

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 के तहत व्यभिचार **अपराध** था।
- इसमें केवल पुरुष को दंडित किया जाता था, महिला को नहीं।
- यह महिला को पति की **संपत्ति जैसा मानता था**।

निर्णय (Judgment) Supreme Court of India ने निर्णय दिया कि:

- धारा 497 IPC **असंवैधानिक (unconstitutional)** है।
- यह **अनुच्छेद 14 (समानता)** और **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)** का उल्लंघन करती है।
- यह **पितृसत्तात्मक सोच (patriarchal thinking)** पर आधारित है।

मुख्य बिंदु

- अब व्यभिचार **अपराध नहीं रहा**।
- लेकिन यह अभी भी **तलाक का आधार** है।

- विवाह का अर्थ स्वामित्व (ownership) नहीं है।

निष्कर्ष इस निर्णय के बाद व्यभिचार को निजी वैवाहिक विवाद माना गया है, न कि आपराधिक अपराध, लेकिन यह तलाक के मामलों में महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

date 01-4-26 time 10.30 am Wednesday period 2

Valid Adoption – Section 6, Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 According to Section 6, no adoption shall be valid unless the following essential conditions are fulfilled:

Essential Conditions

- (a) The person adopting has the **capacity and the legal right** to take a child in adoption.
- (b) The person giving the child in adoption has the **capacity to do so**.
- (c) The person being adopted is **capable of being taken in adoption**.
- (d) The adoption is made in **compliance with the other conditions** laid down in the Act.

Nature of Adoption (Legal + Religious Aspect)

Case Law Hem Singh v. Harnam Singh The court observed that under Hindu law, **adoption is not merely a legal act but also a religious act**, intended to **confer spiritual benefit** upon the adopter, such as continuation of lineage and performance of religious rites.

Conclusion A valid adoption requires **strict compliance with statutory conditions**, and it carries both **legal as well as spiritual significance** in Hindu law.

दत्तक (Adoption) – वैध दत्तक – धारा 6, हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956

धारा 6 के अनुसार, कोई भी दत्तक तभी वैध होगा जब निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी हों:

आवश्यक शर्तें

- (क) दत्तक लेने वाले व्यक्ति के पास दत्तक लेने की क्षमता और अधिकार हो।
- (ख) दत्तक देने वाले व्यक्ति के पास दत्तक देने की क्षमता हो।
- (ग) जिसे दत्तक लिया जा रहा है, वह दत्तक लिए जाने के योग्य हो।
- (घ) दत्तक ग्रहण अधिनियम में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुसार किया गया हो।

दत्तक का स्वरूप (कानूनी एवं धार्मिक पहलू) वाद (Case Law) Hem Singh v. Harnam Singh इस मामले में न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधि में दत्तक केवल एक कानूनी क्रिया नहीं, बल्कि एक धार्मिक कृत्य भी है, जिसका उद्देश्य दत्तक लेने वाले को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना है, जैसे वंश की निरंतरता और धार्मिक कर्तव्यों का पालन।

निष्कर्ष वैध दत्तक के लिए सभी कानूनी शर्तों का पालन आवश्यक है, और यह कानूनी के साथ-साथ धार्मिक महत्त्व भी रखता है।

Section 7 – Capacity of a Male Hindu to Adopt Under **Section 7 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:**

A **male Hindu** who is of **sound mind** and **not a minor** has the capacity to take a child in adoption.

Condition regarding Wife

- If he has a **living wife**, he cannot adopt **without her consent**.
- Consent of wife is **mandatory**, unless:
 - She has **completely and finally renounced the world**, or
 - She has **ceased to be a Hindu**, or
 - She has been **declared of unsound mind by a court**.

If a man has **more than one wife**, the **consent of all wives** is required.

Important Case Laws

1. Krushna Chandra Sahu v. Pradipta Das The court held that **consent of the wife is mandatory**, and adoption without such consent is **invalid**, unless covered by statutory exceptions.

2. Sawan Ram v. Kalawanti The Supreme Court of India held that:

- An adopted child becomes the child of the **adoptive father**.
- However, he **does not automatically become the adopted child of the stepmother** unless she also adopts him.

3. Dhani Chand v. Paras Ram The court emphasized that **valid adoption must strictly comply with legal requirements**, and any deviation may render the adoption **invalid**.

Conclusion Section 7 ensures that adoption by a male Hindu is **valid only when statutory conditions, especially wife's consent, are fulfilled**.

धारा 7 – पुरुष हिंदू की दत्तक लेने की क्षमता हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार: - कोई भी पुरुष हिंदू, जो सद्बुद्धि (sound mind) का हो और अवयस्क (minor) न हो, दत्तक लेने की क्षमता रखता है।

पत्नी की सहमति (Consent of Wife)

- यदि उसकी **पत्नी जीवित है**, तो वह उसकी **सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकता**।
- पत्नी की सहमति आवश्यक है, सिवाय इसके कि:
 - उसने **संन्यास ले लिया** हो, या
 - वह **हिंदू न रही** हो, या

- उसे न्यायालय द्वारा **असामान्य मस्तिष्क (unsound mind)** घोषित किया गया हो।

यदि एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो **सभी की सहमति आवश्यक है।**

महत्वपूर्ण वाद (Case Laws)

1. **Krushna Chandra Sahu v. Pradipta Das** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि **पत्नी की सहमति अनिवार्य है**, और इसके बिना किया गया दत्तक **अवैध होगा**, जब तक कि अधिनियम में दिए गए अपवाद लागू न हों।

2. **Sawan Ram v. Kalawanti** Supreme Court of India ने कहा कि:

- दत्तक लिया गया बच्चा **दत्तक पिता का संतान** माना जाएगा।
- वह स्वतः **सौतेली माँ का संतान नहीं बनता**, जब तक कि वह भी उसे दत्तक न ले।

3. **Dhani Chand v. Paras Ram** इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि **वैध दत्तक के लिए सभी कानूनी शर्तों का कड़ाई से पालन आवश्यक है**, अन्यथा दत्तक **अवैध हो सकता है।**

निष्कर्ष धारा 7 यह सुनिश्चित करती है कि पुरुष द्वारा दत्तक **कानूनी शर्तों, विशेषकर पत्नी की सहमति**, के पालन के बाद ही वैध माना जाएगा।

Section 8 – Capacity of a Female Hindu to Adopt A female Hindu has the capacity to adopt if she is:

- Of **sound mind**, and
- **Not a minor**

She can adopt:

- If she is **unmarried**, or
- A **widow**, or
- **Divorced**, or
- Her husband has:
 - Renounced the world, or
 - Ceased to be Hindu, or
 - Been declared of unsound mind

👉 If she has a **living husband**, she **cannot adopt** except in the above situations.

Section 9 – Persons Capable of Giving in Adoption Only the following persons can give a child in adoption:

- **Father** – with the **consent of the mother** (unless exceptions apply)
- **Mother** – if father is dead, has renounced the world, is of unsound mind, or has ceased to be Hindu

- **Guardian** – with **permission of the court**, if both parents are not capable

👉 The welfare of the child is the **paramount consideration**.

Section 10 – Persons Who May Be Adopted A person can be adopted only if:

- He or she is a **Hindu**
- Has **not already been adopted**
- Is **not married** (unless custom permits)
- Is **below 15 years of age** (unless custom allows otherwise)

Section 11 – Other Conditions for a Valid Adoption

- If adopting a **son**, the adopter must not already have a **living son/son's son/son's son's son**
- If adopting a **daughter**, the adopter must not already have a **living daughter**
- If a male adopts a female, there must be **at least 21 years age difference**
- If a female adopts a male, there must be **at least 21 years age difference**
- There must be an actual act of **giving and taking (datta homam not essential)**

Conclusion Sections 8–11 ensure that adoption is **legally valid, ethical, and in the best interest of the child**.

धारा 8 – महिला हिंदू की दत्तक लेने की क्षमता - कोई भी महिला हिंदू दत्तक ले सकती है यदि:

- वह **सद्बुद्धि (sound mind)** की हो, और
- **अवयस्क (minor) न हो**

वह दत्तक ले सकती है यदि:

- वह **अविवाहित** हो, या
- **विधवा** हो, या
- **तलाकशुदा** हो, या
- उसके पति:
 - **संन्यासी** हो गए हों, या
 - **हिंदू न रहे हों**, या
 - **असामान्य मस्तिष्क घोषित** किए गए हों

👉 यदि पति जीवित है, तो सामान्यतः महिला **स्वतंत्र रूप से दत्तक नहीं ले सकती**।

धारा 9 – दत्तक देने की क्षमता दत्तक देने का अधिकार निम्न को है:

- पिता – माता की सहमति से
- माता – यदि पिता मृत हो, संन्यासी हो, हिंदू न रहा हो या असामान्य मस्तिष्क का हो
- अभिभावक (Guardian) – न्यायालय की अनुमति से

👉 बच्चे का कल्याण (welfare) सर्वोपरि माना जाता है।

धारा 10 – दत्तक लिए जाने की योग्यता कोई व्यक्ति दत्तक लिया जा सकता है यदि:

- वह हिंदू हो
- पहले से दत्तक न लिया गया हो
- विवाहित न हो (जब तक प्रथा अनुमति न दे)
- उसकी आयु 15 वर्ष से कम हो (जब तक प्रथा अनुमति न दे)

धारा 11 – वैध दत्तक की अन्य शर्तें

- पुत्र को दत्तक लेने पर पहले से जीवित पुत्र/पौत्र/प्रपौत्र नहीं होना चाहिए
- पुत्री को दत्तक लेने पर पहले से जीवित पुत्री नहीं होनी चाहिए
- विपरीत लिंग के दत्तक में कम से कम 21 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए
- देने और लेने की वास्तविक क्रिया (giving and taking) आवश्यक है (दत्त होम आवश्यक नहीं)

निष्कर्ष - धारा 8–11 दत्तक को वैध, नैतिक और बच्चे के हित में सुनिश्चित करती हैं।

1. Sri Krishori Lal v. Chaltibai

Principle The Supreme Court of India held that:

- For a valid adoption, there must be **clear proof of the actual act of “giving and taking”** of the child.
- Mere intention or documents are **not sufficient** without this essential ceremony.

👉 Thus, the **ceremony of giving and taking (Datta Homam not mandatory)** is crucial to validate adoption.

2. Gurudas v. Rasaranjan Principle - The Supreme Court held that:

- Adoption must be **strictly proved**, as it changes the **course of succession and inheritance**.
- The person claiming adoption must establish it with **clear, cogent, and satisfactory evidence**.

👉 Adoption cannot be presumed; it must be **proved like an important legal fact**.

Conclusion - These cases emphasize that:

- **Actual giving and taking is essential**, and

- **Strict proof is required** due to serious legal consequences of adoption.

1. **Sri Krishori Lal v. Chaltibai सिद्धांत (Principle)** - Supreme Court of India ने कहा कि:

- वैध दत्तक के लिए **बच्चे को देने और लेने की वास्तविक क्रिया (giving and taking)** का प्रमाण आवश्यक है।
- केवल इरादा या दस्तावेज **पर्याप्त नहीं हैं** जब तक यह क्रिया सिद्ध न हो।

👉 इसलिए, **देने और लेने की प्रक्रिया** दत्तक को वैध बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है (दत्त होम अनिवार्य नहीं है)।

2. **Gurudas v. Rasaranjan सिद्धांत (Principle)** -सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

- दत्तक को **कड़ाई से सिद्ध (strict proof)** करना आवश्यक है, क्योंकि यह **उत्तराधिकार (inheritance)** को प्रभावित करता है।
- दत्तक का दावा करने वाले व्यक्ति को इसे **स्पष्ट और ठोस साक्ष्य (clear and cogent evidence)** से साबित करना होगा।

👉 दत्तक को अनुमान के आधार पर नहीं माना जा सकता; इसे **पुख्ता रूप से सिद्ध करना आवश्यक है।**

निष्कर्ष - इन मामलों से स्पष्ट होता है कि:

- **देने और लेने की क्रिया अनिवार्य है, और**
- **दत्तक को सख्ती से सिद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि इसके गंभीर कानूनी प्रभाव होते हैं।**

Meaning of Inheritance Inheritance refers to the **devolution of property** of a deceased person upon his/her legal heirs. It is mainly governed by the **Hindu Succession Act**.

Types of Inheritance

1. **Intestate Succession** – When a person dies **without a will**
2. **Testamentary Succession** – When a person dies **with a will**

Key Principles

- Property devolves upon **Class I heirs** first (son, daughter, widow, mother).
- **Daughters have equal rights** as sons (after amendment).
- Welfare and rights of children are **paramount** in inheritance-related disputes.

Important Case Laws

1. **Githa Hariharan v. Reserve Bank of India**

- Issue: Whether mother can be a natural guardian during father's lifetime.

- Held: Mother can act as **natural guardian** if father is absent or not capable.
👉 Strengthened **women's rights in family and property matters**.

2. **Rosy Jacob v. Jacob A Chakramakkal**

- Held: **Child welfare is paramount**, not parental rights.
👉 Important in inheritance and custody-related disputes.

3. **Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal**

- Held: In matters of children, **welfare of child overrides all other considerations**.

4. **Mausami Moitra Ganguli v. Jayant Ganguli**

- Court emphasized **holistic welfare of the child** (emotional, moral, educational).

5. **Nil Ratan Kundu v. Abhijit Kundu**

- Welfare includes **ethical and moral upbringing**, not just financial capacity.

6. **ABC v. State (NCT of Delhi)**

- Held: An **unwed mother can be sole guardian** without disclosing father's identity.
👉 Strengthens rights of **single mothers and children**.

Conclusion Inheritance law ensures **fair distribution of property**, while courts emphasize **equality and welfare of children**, especially in modern interpretations.

उत्तराधिकार (Inheritance) का अर्थ उत्तराधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी **संपत्ति का उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में वितरण**। यह मुख्यतः **Hindu Succession Act** द्वारा नियंत्रित होता है।

उत्तराधिकार के प्रकार

1. **बिना वसीयत (Intestate Succession)**
2. **वसीयत के साथ (Testamentary Succession)**

मुख्य सिद्धांत

- संपत्ति पहले **Class I heirs** (पुत्र, पुत्री, विधवा, माता) को मिलती है।
- पुत्री को भी **पुत्र के समान अधिकार** प्राप्त हैं।
- बच्चों का **कल्याण सर्वोपरि** माना जाता है।

महत्वपूर्ण वाद (Case Laws)

1. **Githa Hariharan v. Reserve Bank of India**

- निर्णय: माता भी पिता के जीवित रहते हुए **प्राकृतिक अभिभावक** हो सकती है।
👉 महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया गया।

2. Rosy Jacob v. Jacob A Chakramakkal

- निर्णय: बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, न कि माता-पिता का अधिकार।

3. Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal

- निर्णय: बच्चे के मामलों में उसका हित सबसे महत्वपूर्ण है।

4. Mausami Moitra Ganguli v. Jayant Ganguli

- निर्णय: बच्चे के समग्र विकास (भावनात्मक, नैतिक, शैक्षिक) को महत्व दिया गया।

5. Nil Ratan Kundu v. Abhijit Kundu

- निर्णय: बच्चे के नैतिक और सामाजिक विकास को भी महत्व दिया गया।

6. ABC v. State (NCT of Delhi)

- निर्णय: अविवाहित माता को एकल अभिभावक (sole guardian) माना गया।

निष्कर्ष उत्तराधिकार कानून संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है, जबकि न्यायालयों ने बच्चों के कल्याण और समानता को सर्वोच्च महत्व दिया है।

*****=====*****=====*****=====*****

date 16.4.26 time Thursday

hindu succession act 1956 Introduction The **Hindu Succession Act** was enacted to **codify and amend the law relating to intestate succession** among Hindus. It applies to **Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs**. The Act brought **uniformity and gender justice**, especially after the **2005 Amendment**, which granted daughters equal rights in coparcenary property.

Objectives of the Act

- To provide a **uniform system of inheritance**
- To remove **gender discrimination**
- To ensure **fair distribution of property**

Types of Succession

1. Intestate Succession

When a person dies **without a will**, property devolves according to the Act.

2. Testamentary Succession

When a person dies **with a will**, property is distributed as per the will (Indian Succession Act applies).

General Rules of Succession (Sections 8–13)

- Property devolves first upon **Class I heirs**:
 - Son, daughter, widow, mother, etc.
- In absence of Class I heirs → **Class II heirs**

- Then → **Agnates and Cognates**

Coparcenary Rights (Amendment 2005)

- Daughters are now **equal coparceners** by birth.
- They have the same **rights and liabilities** as sons.

Property of Female Hindu (Sections 14–16)

- A female Hindu becomes the **absolute owner** of property (**Section 14**).
- Property devolves first to:
 - Sons, daughters, husband

Important Case Laws

1. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma

- Held: Daughters have **equal coparcenary rights by birth**, irrespective of father's death.

2. Githa Hariharan v. Reserve Bank of India

- Strengthened **women's rights** in family property matters.

3. Danamma v. Amar

- Recognized **daughter's right in ancestral property**.

4. Prakash v. Phulavati

- Initially limited application of amendment, later clarified in Vineeta Sharma case.

Conclusion The Hindu Succession Act, 1956 ensures **equitable distribution of property** and promotes **gender equality**, especially after judicial interpretation and amendments.

परिचय **Hindu Succession Act** हिंदुओं में **बिना वसीयत (intestate succession)** के मामलों में संपत्ति के उत्तराधिकार को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया कानून है। यह **हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख** पर लागू होता है। 2005 के संशोधन के बाद इस अधिनियम ने **महिलाओं को समान अधिकार** प्रदान किए।

उद्देश्य

- उत्तराधिकार में **एकरूपता लाना**
- **लैंगिक भेदभाव समाप्त करना**
- संपत्ति का **न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना**

उत्तराधिकार के प्रकार

- 1. बिना वसीयत (Intestate Succession)** जब व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है।
- 2. वसीयत के साथ (Testamentary Succession)** जब व्यक्ति वसीयत बनाकर मरता है।

सामान्य नियम (धारा 8–13)

- संपत्ति पहले **Class I heirs** को मिलती है:
 - पुत्र, पुत्री, विधवा, माता आदि
- इनके अभाव में → **Class II heirs**
- फिर → **Agnates और Cognates**

सहभोजी (Coparcenary) अधिकार – 2005 संशोधन

- पुत्री को जन्म से समान अधिकार दिया गया।
- पुत्र के समान अधिकार और दायित्व।

महिला की संपत्ति (धारा 14–16)

- महिला अपनी संपत्ति की **पूर्ण स्वामिनी (absolute owner)** होती है।
- उसकी संपत्ति पहले:
 - पुत्र, पुत्री, पति को मिलती है।

महत्वपूर्ण वाद (Case Laws)

1. **Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma** निर्णय: पुत्री को जन्म से समान अधिकार प्राप्त हैं।
2. **Githa Hariharan v. Reserve Bank of India** महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया गया।
3. **Danamma v. Amar** पुत्री के पैतृक संपत्ति में अधिकार को मान्यता दी गई।
4. **Prakash v. Phulavati** बाद में Vineeta Sharma केस द्वारा स्पष्ट किया गया।

निष्कर्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने संपत्ति के न्यायसंगत वितरण और महिलाओं की समानता को सुनिश्चित किया है, जो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

*****=====*****

course completed on date 16.4.2026
